दैनिक
नव प्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर
3 राजधानी — छत्तीसगढ़ के लोगों को निकालने रेलवे...
4 अभिव्यक्ति — मोदी पैकेज जमीनी स्तर पर निरर्थक...
9 मनोरंजन/खेल — महिलाओं की मदद के लिये आगे आयी...
11 व्यापार — हर्बल खेती पर खर्च होंगे 4000 करोड़...

www.navpradesh.com | बिलासपुर, शनिवार 16 मई 2020, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष-नवमी , विक्रम संवत-2077 वर्ष-06 अंक-36 पृष्ठ-12 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

जिन नियोक्ताओं ने लाखों प्रवासी मजदूरों को सड़क पर ला दिया है उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। न ही सरकार इन मजदूरों को तात्कालीन राहत पहुंचा रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए एक दूसरे के सिर पर ठिकरा फोड़ रही हैं। जबकि मजदूरों की दुर्दशा के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। नई दिल्ली से सर्वाधिक प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं और नई दिल्ली सरकार प्रतिदिन दस लाख मजदूरों को खाना खिलाने का दावा कर रही है। यही हाल अन्य राज्य सरकारों का है। सभी ने मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

कंटेनमेंट को छोड़ शेष में जरूरी के साथ ही गैर आवश्यक सामानों की हो बिक्री

नव प्रदेश संवाददाता

- मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 3 के बाद की रणनीति को लेकर पीएम मोदी को दिए कई सुझाव
- होटल व्यवसाय को सिर्फ रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने की दी जा सकती है अनुमति
- हर सुझाव के लिए फिजिकल डिस्टंसिंग की शर्त का भी उल्लेख

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन 3 के उपरांत आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ही ये सुझाव मांगे गए थे। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। वाहनों की बिक्री करने वाले समस्त प्रकार के शोरूम एवं वर्कशाप संचालन की अनुमति हो। समस्त प्रकार के ई-कामर्स

■ शेष पृष्ठ 8 पर

ये मांग भी की प्रधानमंत्री से

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन तथा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले परिवहन व्यय के भुगतान हेतु एसडीआरएफ(राज्य आपदा मोचन निधि) में समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया है।

नगरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को मिले मंजूरी

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में भी समस्त प्रकार के निर्माण कार्य हेतु अनुमति फिजिकल डिस्टेंस के पालन की शर्त पर देनी चाहिए। इसके लिए श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था के लिए पास की अनुमति होना अनिवार्य किया जा सकता है। राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करे।

अंतरराज्यीय सीमाओं को अभी खोलना उपयुक्त नहीं

उन्होंने लिखा है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य श्रेणीयों के व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। इन व्यक्तियों के आने की सूचना राज्यों के बीच साझा की जानी चाहिए ताकि क्वारेंटीन सहित अन्य आवश्यक उपाय किए जा सकें। गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन ■ शेष पृष्ठ 8 पर

20 लाख करोड़ का पैकेज। केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने तीसरे दिन बताए प्रावधान

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर बदलेगा आवश्यक वस्तु कानून

अनाज, खाद्य तेलों, तिलहन, दालें, प्याज, आलू आदि इस कानून के दायरे से होंगे बाहर

नई दिल्ली/ नवप्रदेश। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन ब्योरा दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पैकेज में किस तरह से किसानों की आय बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनाज, खाद्य तेलों, तिलहन, दालें, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर निकालने का बड़ा फैसला किया है। आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें अपने उत्पाद कहीं भी बेच पाने की अनुमति देने वाले कानूनी सुधार का भी ऐलान किया। ये घोषणाएं आत्मनिर्भर अभियान के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के विस्तृत ब्योरे के लगातार तीसरे दिन की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गईं। असगंठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य उद्योग (माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज) इकाइयों ■ शेष पृष्ठ 8 पर

कृषि सुधार के लिए 11 कदमों की घोषणा

वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के कारण दबाव में आए खेती और सहायक गतिविधियों मसलन मछलीपालन और पशुपालन आदि के लिए पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 11 कदमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से पहले 8 कदम कृषि संबंधित आधारभूत ढांचों का निर्माण, क्षमता विकास और कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन आदि को लेकर हैं, वहीं आखिरी तीन कदम शासन-प्रशासन से संबंधित हैं।

फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

किसान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड जल्द ही बनाया जाएगा। इससे भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म हो जाएगी।

पशुपालन के लिए 15 हजार करोड़

ऐनिमल हस्बेंड्री इन्फ्राक्ट्रस्चर डिवेलपमेंट फंड के तहत दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने, वैल्यु अडीशन करने आदि के लिए 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इधर सीएम बोले पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त

पिछले 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, रोज़ एक-एक वर्ग के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं परन्तु पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा है, जब ये धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा।

भगवान बदरीनाथ के कपाट खुले

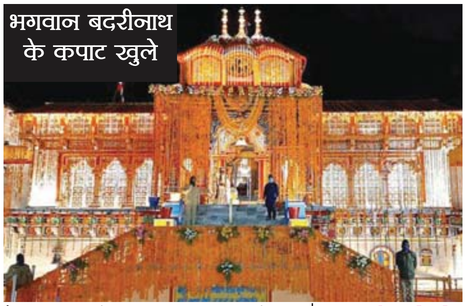

देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को तड़के साढ़े चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान बदरीनाथ धाम के कपाट खोल दिये गये। इस मौके पर बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी तथा अन्य पूजा स्थलों से जुड़े 11 लोग मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से इतिहास में पहली बार कपाट खुलते समय श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। भगवान बदरीनाथ के कपाट को ज्येष्ठ माह, कृष्ण अष्टमी तिथि, कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र, ऐंद्रधाता योग के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और मास्क पहने गए।

सुनाई नहीं दी स्वर लहरियां

इस बार भगवान बदरीनाथ के कपाट खुलते समय सेना के बैंड की सुमधुर ध्वनि, भक्तों का हुजूम, भजन मंडलियों की स्वर लहरियां सुनायी नहीं दी।

अच्छी खबर

विश्व बैंक का भारत को एक अरब डॉलर का पैकेज

वाशिंगटन/ (वार्ता)। विश्व बैंक ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से भारत के सर्वाधिक प्रभावित गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए एक अरब डॉलर का सामाजिक संरक्षण पैकेज मंजूर किया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 14 मई की बैठक में इस पैकेज को स्वीकृति दी। इसे मिलाकर विश्व बैंक की कोविड-19 महामारी चुनौती से निपटने के लिए भारत को दी जा रही मदद दो अरब डॉलर हो गई। एक अरब डॉलर की त्वरित मदद पिछले माह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई थी। नये पैकेज की राशि दो किस्तों में दी जायेगी।

कोरोना अपडेट

देश	टोटल केस	मौत
भारत	83,924	2,696
अमेरिका	1,459,684	86,970
ब्रिटेन	233,151	33,614
इटली	223,096	31,368
स्पेन	274,367	27,459
फ्रांस	178,870	27,425
ब्राजील	204,795	14,058
बेल्जियम	54,644	8,959
जर्मनी	168,276	7,277
ईरान	116,635	6,902
नीदरलैंड	43,681	5,643
कनाडा	73,401	5,472
मैक्सिको	42,595	4,477
टर्की	144,749	4,007
स्वीडन	29,207	3,646
स्वीट्जरलैंड	30,514	1,874

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 31097.73
निफ्टी- 9136.85
गोल्ड- 47140 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 46006 (1 कि ग्रा.)

कोरोना से मरने वाले 3 लाख के पार

नई दिल्ली/नवप्रदेश। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण से देश में 3 लाख 3 हजार 863 लोगों की जान चली गई है। वहीं दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़कर 45 लाख 46 हजार 70 पहुंच गया है। भारत की बात करें तो यहां मरने वालों की ■ शेष पृष्ठ 8 पर

भारत की राह में अब रोड़ा अटकाने की कोशिश में लगा नेपाल

- उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख तक रोड लिंक बनाये जाने का विरोध कर रहा पड़ोसी देश
- भारतीय राजदूत को किया तलब

नवप्रदेश दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। अब एक और पड़ोसी देश नेपाल भारत की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है जिससे वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे भारत के सामने एक और चुनौती खड़ी हो सकती है। नेपाल ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख तक रोड लिंक बनाये जाने के विरोध में सोमवार को अपने यहां भारतीय राजदूत को समन जारी किया है। नेपाल ऐसा तब कर रहा है जब चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने तथा पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए सेना प्रमुख की प्रतिबद्धता जताई जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में सड़क निर्माण को लेकर चीन और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भारत के खिलाफ विरोध जताया है।

नेपाल का दावा

नेपाल सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारतीय राजूदत वी एम क्वात्रा को राजनयिक पत्र सौंपा। नेपाल सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में जो सड़क बनायी गयी है, वह उसके क्षेत्र में है।

भारत ने किया खारिज

दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाल ही जिस रोड का उद्घाटन किया गया है वह पूरी तरह से भारत की सीमा में है। इस मार्ग पर आवागमन आसान हो जाने से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और व्यापारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी।

पूरा वेतन नहीं देने वाली कंपनियों को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश पर लगाई रोक, नहीं चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली/ए.। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं (एंप्लॉयर्स) के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

केंद्र से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बी.आर. गवई की पीठ ने केंद्र और राज्यों से मजदूरी का भुगतान न कर पाने पर निजी कंपनियों, कारखानों आदि के खिलाफमुकदमा नहीं चलाने को कहा। शीर्ष अदालत ने औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दें।

औद्योगिक इकाइयों ने पेमेंट पर फैसला लेने की छूट मांगी

औद्योगिक इकाइयां यह दावा करते हुए अदालत चली गई कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष ■ शेष पृष्ठ 8 पर

कार्रवाई

नमक की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी को भेजा जेल

जगदलपुर /नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में नमक की कालाबाजारी करते गिरफ्तार किए गए एक कारोबारी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नमक की कृत्रिम किल्लत पैदा कर इसके दाम बढ़ाकर बेचने वाले नमक कारोबारी गोविंद राव के खिलाफ बुधवार की देर रात एफआईआर दर्ज की गयी। इसके बाद कल उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, नगर निगम और नापतौल विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को प्रतापगंजपारा स्थित एक नमक कारोबारी के यहां दबिश में सरकारी अमृत नमक 1150 किलो जब्त किया था।

गरमा-गरम

पड़ताल राष्ट्रीय महिला आयोग कर चुका लॉकडाउन के 25 दिन में ही घरेलू हिंसा की शिकायतों में 95 फीसदी के इजाफे का दावा

लॉकडाउन में राज्य महिला आयोग को कम मिलीं शिकायतें

रायपुर/नवप्रदेश। लॉकडाउन के दौरान जहां एक ओर देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं वहीं छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा शिकायतें बढ़ी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में पहले की तुलना में कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो इससे निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन में प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामलों में अन्य राज्यों की तुलना में कमी ही आ गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग में अधिकतर आवेदन डाक से प्राप्त होते हैं। आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन काफी कम प्राप्त ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सामान्य दिनों में मिलते थे 70-80 आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सहायक संचालक अभय कुमार देवांगन ने नवप्रदेश को बताया कि सामान्य दिनों में आयोग को हर दिन ऑनलाइन व डॉक के मिलाकर 70-80 शिकायती आवेदन प्राप्त होते थे। इनमें आधे से ज्यादा दहेज व घरेलू हिंसा के होते थे। इनमें से परीक्षण के बाद 40-50 शिकायतों पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित थानों व जिले के संरक्षण अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि आयोग को प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या करीब आधी हो गई है। इसके पीछे के कारण लॉकडाउन में डाक से आवेदन नहीं पहुंच पाना हो सकता है।

जानें छत्तीगढ़ में कम शिकायतों की वजह

देवांगन के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग में अधिकतर मेट्रो सिटीज से ऑनलाइन शिकायतें की जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसे शहरों की महिलाओं की तरह ऑनलाइन सेवा उपभोक्ताओं की संख्या कम हैं। आम दिनों में भी प्रदेश के महिला आयोग में आनलाइन शिकायतें कम ही प्राप्त होती है। आदिवासी अंचलों से तो डाक से ही शिकायतें प्राप्त होती हैं। डाक सेवा फिर से सुचारू होने के बाद हो सकता है कि मामले बढ़ जाएं लेकिन अभी की स्थिति में तो शिकायतें कम ही प्राप्त हुई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग कर चुका है ये दावा

पूरे देश की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देशभर में घरेलू हिंसा के मामले 95 फीसदी तक बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग देशव्यापी बंद से पहले और बाद के 25 दिनों में विभिन्न शहरों से मिली शिकायतों के आधार पर यह दावा किया है। आयोग की मानें तो महिलाओं से घरेलू हिंसा के मामले लगभग दोगुने बढ़ गए हैं। आयोग ने इस साल 27 फरवरी से 22 मार्च के बीच और लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच मिली शिकायतों की तुलना के बाद के आंकड़ों के आधार पर ■ शेष पृष्ठ 8 पर

संपत्ति कर और विवरणी जमा करने फिर मिली छूट

- अब 31 मई तक संपत्ति कर और विवरणी जमा किए जा सकेंगे

रायपुर (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए लोगों को एक बार फिर से विशेष छूट देते हुए जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 31 मई कर दिया है। पूर्व में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की तिथि 15 मई 2020 निर्धारित की गई थी। राज्य शासन ने इसे अब 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। नागरिक अब संपत्ति कर और विवरणी 31 मई तक जमा कर सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि संपत्ति कर जमा करने आने वाले नागरिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

पैदल घर लौट रहे इन मजदूरों की नाराजगी पड़ सकती है भारी

लॉकडाउन के बावजूद अपने घरों की तरफ पैदल निकल पड़े हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर

■ रास्ते में लाख परेशानियां झेलीं, ना खाने को ठीक से मिला, ना पीने को पानी

■ लॉकडाउन की वजह से दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा भारतीय समाज

■ बीजेपी को सता रहा डर, कहीं गरीबों की नाराजगी का असर चुनावी नतीजों पर न पड़े

नई दिल्ली (ए.)। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग गुरुवार को पार्टी चीफ जेपी नड्डा के घर पर हुई। लॉकडाउन की घोषणा के बाद, बीजेपी के बड़े नेता पहली बार मिले हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश के कोरोना से उपजे हालात पर चर्चा के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। मगर इसमें मुद्दा छाया रहा प्रवासी मजदूरों का। पार्टी अपने नेताओं से यही जानना चाहती थी कि जो हालात अभी बने हैं, उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे रोड पर मौजूद मजदूरों की यथासंभव मदद करें। बीजेपी अब प्रवासी मजदूरों की सुध क्यों ले रही है? इसके पीछे पार्टी का एक डर बड़ी वजह है। वो डर है अपना वोट-बैंक खोने का।

पीएम का भी श्रमिकों पर जोर

तीन दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि 'हमारे रेहड़ी, ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, श्रमिक साथी हैं, घरों में काम करने वाले भाई-बहन हैं। उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन है जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का।' उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे मजदूरों को उनके राज्य भेजने की व्यवस्था करें क्योंकि उन्होंने घर लौटने का मन बना लिया है।

लगातार बना हुआ है संकट

24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। रात 8 बजे का यह ऐलान महज चार घंटों बाद, 25 मार्च की रात से लागू हो गया। उस वक्त शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि माइग्रेशन की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार को स्थिति की भयावहता का अंदाजा शायद अप्रैल के आखिरी दिनों में हुआ। तभी तो 1 मई से 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया। मगर प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में थी। आधा मई गुजर चुका है और मजदूर अबतक सड़कों पर हैं। उनके भीतर गुस्सा है क्योंकि जब उन्हें सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे ठोकर खाने को मजबूर थे। बीजेपी शायद इस बात को महसूस कर पा रही है। इस मुद्दे पर अब वह बैकफुट पर है। देश के बंटवारे के बाद पलायन का ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया था। इसलिए बीजेपी को टेंशन होनी लाजिमी है।

गरीब ही बनाते-बिगाड़ते हैं सरकार

मार्च में एक सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में कहा था कि देश में करीब 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से बहुतों को लॉकडाउन ने गहरी चोट दी है। भारत में वोटिंग के पैटर्न को देखें तो यह गरीब तबका किंगमेकर की भूमिका में रहता है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 2014 के मुकाबले अपना बेस मजबूत किया है। उसका वोट शेयर 31.1% से बढ़कर 37.4% हो गया। देश के एक-तिहाई (34%) दलितों ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया। गांवों में भी बीजेपी का वोट 7.4 पर्सेंटेज पॉइंट्स बढ़ा।

कहीं खो ना जाए बीजेपी की बढ़त

आर्थिक रूप से कमजोर तबका बीजेपी के चुनावी पराक्रम की मुख्य वजह रहा है। 2014 से शुरू हुई वो लहर 2019 में और मजबूत ही हुई। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग साइंस की 2019 और 2014 के नतीजों पर रिसर्च बताती है कि गरीब तबके के वोटों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा फायदा हासिल किया। 2014 में बीजेपी को गरीबों के बीच जहां 24 फीसदी वोट मिले थे, 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36त हो गया। प्रवासी मजदूरों के संकट से बीजेपी को सबसे बड़ा डर इसी बढ़त को खोने का है।

दिल्ली के सेना भवन में मिला कोरोना का मरीज, इमारत का एक हिस्सा सील

नई दिल्ली (ए.)। दिल्ली के सेना भवन में एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इमारत का एक हिस्सा सील कर दिया गया है। वहीं, उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। सेना भवन के जिस हिस्से में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिला है, उसे पूरी तरह से बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल महीने में राजीव गांधी भवन में भी कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस सामने आया था। इसके बाद इमारत के एक हिस्से को बंद कर दिया गया था। वहीं, पिछले दिनों एयर इंडिया के दिल्ली दफ्तर में भी कोरोना का मरीज मिल चुका था।

गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत, सुको से राहत

अहमदाबाद । सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा का निर्वाचन रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने भूपेंद्र सिंह चूडासमा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही पीठ ने भूपेंद्र सिंह चूडासमा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किए। याचिका में क्याः अपील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि इस चुनाव में पराजित कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विन राठौड़ ने किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस और भरोसेमंद साक्ष्य पेश नहीं किया। भाजपा के इस नेता ने अपनी अपील में कहा है कि इसलिए गुजरात विधानसभा के लिए 14 दिसंबर, 2017 को हुए चुनाव में ढोलकिया सीट से वह विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाने के हकदार नहीं थे।

क्वारंटाइन में कोरोना योद्धा कैसे रह रहे हैं और व्यवस्था कैसी है?

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (ए.)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के अस्पतालों के निकट ही पृथकवास (क्वारंटाइन) के लिए उठाये गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूति बी आर गवई की पीठ ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केन्द्र को यह निर्देश दिया। पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस बारे में जानकारी प्राप्त करके अगले सप्ताह उसे अवगत करायें।

कमरे, बाथरूम साझा करने पड़ रहे

इस मामले में याचिकाकर्ता डा आरूषि जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के रेजिडेन्ट डाक्टरों को सात से 14 दिन की ड्यूटी करने के बाद पृथकवास किया जाना चाहिए। लेकिन इन चिकित्सकों को उन स्थानों पर पृथकवास कराया जा रहा है जहां उन्हें कमरे, बाथरूम साझा करने पड़ रहे हैं जबकि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामाजिक दूरी बनी रहे।

कोरोना योद्धाओं को मकान खाली कराना बने गैर जमानती अपराध

मेहता ने कहा कि सरकार इन कोरोना योद्धाओं की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और इस बारे मे निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों पर किसी भी प्रकार के हमले या उन्हें मकान अथवा आवासीय सोसायटी के फ्लैट खाली करने के लिये कहने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पीठ ने मेहता से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अस्पतालों के निकट ही पृथकवास के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में दिये गए सुझाव पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ सुझाव विचाराधीन हैं और यह इनमें से एक है। रोहतगी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सालिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वह बहुत कम है लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि कितने होटल और आवास उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि वे अपनी किसी भी समस्या के बारे में प्राधिकारियों को अवगत करा सकें।

कोरोना योद्धाओं को सुविधाएं दी जाएं

रोहतगी ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पृथकवास के मकसद को ही विफल करेगी और कोरोना योद्धा बीमार पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ यह चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में मौजूद इन स्वास्थ्यकर्मियों को अस्पतालों के नजदीक आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि डाक्टरों के लिये भी एक निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए क्योंकि ये अपने घरों से अस्पताल पहुंचने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आवास सोसायटियों में भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अगले सप्ताह पीठ करेगी विचार

पीठ ने मेहता से कहा कि वह इस मामले में अब अगले सप्ताह विचार करेगी और उस समय तक उन्हें अस्पतालों के नजदीक ही डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के पृथकवास की सुविधाओं के बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों का इलाज कर रहे डाक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इस युद्ध में पहली पंक्ति के योद्धा हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिये जरूरी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहें।

सरकार बोली- आवश्यक कदम उठाए गए हैं

सालिसिटर जनरल ने कहा कि इन डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त संख्या में होटल और अतिथि गृहों की व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन अगर कहीं कोई विसंगति है तो उसमें सुधार के लिये उसे प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की राज्यों से अपील

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगाएं रोक

नई दिल्ली (ए.)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की यह अपील कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का मामला 80 हजार के पार पहुंच गया है।

पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत

देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,649 तक पहुंच गई है। वहीं बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे से संक्रमण के 3,967 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद शुक्रवार को कुल संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 51,401 लोगों का उपचार चल रहा है जबकि अब तक 27,919 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है।

अब तक 34.06 फीसदी मरीज स्वस्थ हो गए

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक 34.06 फीसदी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे से 100 लोगों की मौत हुई। इनमें से सबसे ज्यादा 44 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, गुजरात में 20, दिल्ली में 9, पश्चिम बंगाल में आठ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पांच-पांच, राजस्थान में चार, तमिलनाडु और कर्नाटक में दो-दो तथा आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई।

देश में अब तक इस वायरस की वजह से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 1,019, गुजरात में 586, मध्य प्रदेश में 237, पश्चिम बंगाल में 215, राजस्थान में 125, दिल्ली में 115, उत्तर प्रदेश में 88, तमिलनाडु में 66 और आंध्र प्रदेश में 48 लोगों की मौत हुई।

ट्रेन के बाद अब दिल्ली मेट्रो चलाने की तैयारी

नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन के कारण थम चुकी दिल्ली मेट्रो को फिर से चलाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज बताया कि लॉकडाउन के दौरान मेट्रो के जितने भी हमारे ट्रैक और रूट हैं उनपर एक-एक ट्रेन चलाकर हमने देखा, ताकि सिस्टम चलता रहे। जो ट्रेनें नहीं चली हैं, उनकी पूरी जांच की जाएगी और सर्टिफिक्रेट दिया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली मेट्रो को चलाने का फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। कैलाश गहलोत ने बताया कि हर स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। नोटों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी स्टेशन पर भीड़ होती है तो एंट्री बंद कर दी जाएगी।

प्रमुख स्टेशन को ही खोला जाएगा ताकि पूरा मैन पावर लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। दिल्ली सरकार को लॉक डाउन के दौरान मेट्रो और सीमित संख्या में बसें चलाने का सुझाव मिला है। दिल्ली सरकार के मुताबिक उन्हें इस दौरान दिल्ली के बाजार खोले जाने को लेकर भी कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, लॉकडाउन 4.0 में दी जाने वाली जरूरी ढील को लेकर दिल्ली की जनता से मिले सुझावों पर विचार के उपरांत प्रस्ताव बना कर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है।''

उन्होंने कहा, ''जनता से बहुत सारे सुझाव आए थे। ज्यादातर लोगों ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया है। पहला, मास्क है। लोगों ने सुझाव दिया है कि जब भी कोई घर से बाहर निकले, वह मास्क जरूर पहनें और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग है। जो भी चीजें खोली जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।

विधायक रामेश्वर शर्मा बोले साध्वी प्रज्ञा को एक आंख से दिखना बंद

भोपाल (ए.)। कोरोना महामारी के बीच भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने जरूर कुछ ट्वीट किए थे, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि इस दौर में भोपाल सांसद का गायब होने दुर्भाग्य है। पीसी शर्मा ने सांसद को लापता घोषित कर दिया। इसे लेकर राजनीति तेज हुई, तो साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस को जवाब दिया है। साथ ही बताया भी है कि वह कहां हैं। दरअसल, भोपाल दक्षिण-पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि संकट के समय में भोपाल सांसद का गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मा के आरोपों पर पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में साध्वी प्रज्ञा को काफी प्रताड़ित किया गया था। वह उससे पीड़ित हैं, उन्हें रासायनिक इंजेक्शन दिया गया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा की एक आंख में रिएक्शन हो गया है, वो खुलना बंद हो गया है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें काफी टॉर्चर किया गया था।

भारत में ही बनेंगे एयरक्राफ्ट, विदेशों से नहीं आएंगे करोड़ों के विमान

दो साल पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वारप्लेन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी

■ इसके तहत ग्लोबल कंपनियों से 114 लड़ाकू एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए प्रपोजल देने को कहा था

नई दिल्ली (ए.)। पीएम मोदी ने इसी हफ्ते 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की बात कही है और भारत अब लोकल मेड फाइटर जेट्स बनाने की सोच रहा है। जबकि दो साल पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वारप्लेन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जिसके तहत ग्लोबल कंपनियों से 114 लड़ाकू एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए प्रपोजल देने को कहा था। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में हल्के लड़ाकू विमान शामिल करना चाहती है जो भारत में ही बने हों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट हमारे पुराने होते विमानों के बेड़े की क्षमता को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना अब 6 अरब डॉलर में 83 जेट खरीदेगी, जो पहले 40 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली थी।

रावत ने कहा कि इंडियन एयर फोर्स ने कहा है कि वह भारत में ही बने फाइटर विमान इस्तेमाल करेगी। ये फैसला बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और साब एबी जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका

है, जो 15 अरब डॉलर की डील के लिए रेस में शामिल थे। ये एक इशारा है कि भारत अब महंगे विदेशी विमानों से किनारा करने की सोच रहा है, जिनकी वजह से पैसों की दिक्कत भी होती थी।

डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा भारत

दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एयरपावर स्टडीज़ के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल मनमोहन बहादुर ने कहा- अब जब भारत में ही बने एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने का फैसला कर ही लिया गया है तो रक्षा मंत्रालय को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता बढ़ानी होगी, जो भारत में जेट बनाती है। रावत ने ये भी कहा कि अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह भी एक बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि यहां कीमतें काफी कम हैं। जब दुनिया भारत को इन विमानों का इस्तेमाल करते देखेगी, तो बेशक ही कुछ देश इसे खरीदने में रुचि लेंगे। फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया करीब एक दशक पहले शुरू हुई थी। भारत ने 2015 में डसॉल्ट एविएशन से 11 अरब डॉलर में 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑर्डर को खत्म किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक 36 प्लेन खरीदे जा चुके हैं, ताकि एयरक्राफ्ट के पुराने विमानों की जगह नए विमान ले सकें।

दो साल पहले 114 जेट खरीदने का निकाला था टेंडर

अप्रैल 2018 में भारत ने 114 जेट खरीदने का एक ग्लोबल टेंडर निकाला था। इसके लिए बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और स्वीडन की साब एबी को अपनी ओर खींचा। दस्तावेजों के अनुसार इनमें से करीब 85 फीसदी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत में ही होना था। वैसे तो मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके एयरफोर्स, नेवी और सेना में अभी भी ऐसे हथियार हैं, जो आज के जमाने में गुजरी बातें हो चुके हैं।

कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा, लॉकडाउन में ढील पड़ सकती है महंगी

लॉकडाउन-3 की मियाद 17 मई को हो रही है खत्म, विशेषज्ञों को आशंका, लॉकडाउन में ढील पड़ सकती है महंगी

बेंगलुरू (ए.)। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने आज कहा कि भारत को कोविड-19 के सामुदायिक स्तर पर फैलने के जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि लॉकडाउन में राहत देने के कारण कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन

(तीसरा चरण) पहले ही शुरू हो चुका है। मगर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि यह परिभाषा पर निर्भर करता है।

कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए तैयार रहे देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81970 पहुंच चुकी है। इनमें से 27920 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं जबकि 2649 की मौत हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग के पूर्व में प्रमुख रहे रेड्डी ने कहा कि यह भी मानना होगा कि सामुदायिक प्रसार हर उस देश में वास्तव में नजर आया है।

कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द से बच रहे हैं विशेषज्ञ

उन्होंने कहा कि अगर हम उन लोगों में प्रसार को देखते हैं जिन्होंने कहीं की यात्रा नहीं की या किसी संक्रमित के संपर्क में नहीं आए, तो निश्चित तौर पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, 'लेकिन ज्यादातर मामले विदेशी यात्रियों के प्रवेश के मूल कारण के इर्द-गिर्द या उनके जानकारों की यात्रा करने से संबंधित हैं। इसलिए जो लोग इसे अब भी दूसरा चरण बता रहे हैं, उनका कहना है कि यह पता लग सकने वाला स्थानीय प्रसार है और ऐसा सामुदायिक प्रसार नहीं है जिसका अनुमान न लगाया जा सके।' उन्होंने कहा कि इसलिए हम सामुदायिक प्रसार जैसे शब्द के इस्तेमाल से बच रहे हैं। यह परिभाषाओं एवं भाषा का विषय है।

छत्तीसगढ़ के लोगों को निकालने रेलवे को 1.17 करोड़ का भुगतान

रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया तथ्यहीन-आधारहीन

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीटर पर जारी बयान का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेल मंत्री री गोयल का बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। छत्तीसगढ़ ने अपने श्रमिकों को निकालने के लिए 1.17 करोड़ का भुगतान रेलवे को कर चुका है। हमने 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ 14 ट्रेन मिली है।

ज्ञात हो कि केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीटर पर एक बयान जारी कर कहा था-रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। जबकि मुख्मयंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ट्वीटर संदेश पर इस बयान का खंडन करते हुए लिखा है।

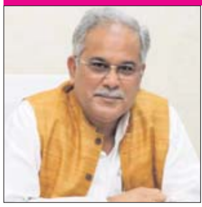

छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 मिली है। ट्रेनों के लिए हम करीब 1.17 करोड़ रूपए का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केन्द्रीय रेल मंत्री जी आपका बयान तथ्यहीन औरर आधारहीन है। इस संदेश के साथ ही सीएम श्री बघेल ने रेलवे को अब तक राज्य सरकार द्वारा तिथिवार किए गए भुगतान का ब्योरा भी पोस्ट किया है। जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों व इलाकों से निकालने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 9 मई को मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे को 1463000 रूपए, 11 मई को पश्चिम रेलवे को ही 1700050 रूपए, 11 और 12 मई को उत्तर रेलवे को क्रमशः 91000, 760320 रूपए, 12 मई कलेक्टर पठानकोट पंजाब उत्तर रेलवे को 1773860 रूपए, 13 मई को उत्तर रेलवे को 828000, 14 मई को पश्चिम रेलवे को 1995290, 14 मई उत्तर रेलवे 760320, 14 मई को ही पश्चिम मध्य रेलवे को 741370 रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

गुजरात : स्पेशल ट्रेन से रायपुर स्टेशन पर उतरे 65 श्रमिक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुजरात के खेड़ा नाडीयाड से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज सबेरे रायपुर स्टेशन पर 65 श्रमिक उतरे। इनमे बलौदाबाजार जिले के 45, धमतरी जिले के 6, राजनांदगांव जिले के 6 और कोंडागांव जिले के 8 श्रमिक शामिल थे। इसके बाद यह ट्रेन बिलासपुर होकर चांपा के लिए रवाना हुई। श्रमिकों के रायपुर स्टेशन आगमन पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें दो-दो बोगियों से बारी-बारी से उतारा गया। यहां सभी श्रमिकों की मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच, थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से उनके तापमान के साथ-साथ पल्स एवं ऑक्सीजन सांद्रता की भी जांच की गई। इसके बाद उन्हें विशेष बसों से उनके जिलों के क्वारेन्टाइन सेन्टर भेजा गया। सभी श्रमिकों ने लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही स्टेशन से बाहर निकले। सभी श्रमिकों को हिदायत दी गई की वे 14 दिन क्वेरेंटाइन में रहें तथा कोरोना से बचाव एवं रक्षा के लिए सभी निर्देशों का पालन करें। श्रमिकों को क्वारेन्टाइन सेन्टर भेजने के बसों की भी व्यवस्था की गयी थी। उन्हें यहां पैक्ड भोजन भी प्रदान किया गया। ट्रेन आगमन के पहले स्टेशन के प्लेटफार्म को सैनिटाइज किया गया।

1481 श्रमिकों को लेकर 21 को मंगलोर से निकलेगी स्पेशल ट्रेन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लगभग 1481 श्रमिकों को लेकर मंगलोर से 21 मई को श्रमिक विशेष ट्रेन रवाना होगी, यह ट्रेन 22 मई को दुर्ग, रायपुर होते हुए बिलासपुर आएगी। राज्य के नोडल अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों के कुल 1481 श्रमिक सवार होंगे जो कि बस्तर तक जाएंगे। इस श्रमिकों को लाने के लिए कर्नाटका के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है कि श्रमिकों से किसी भी प्रकार से शुल्क न लिया जाए तथा उनके आने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलोर से रवाना होकर दुर्ग, रायपुर, भाटापारा रेलवे स्टेशन में रूकते हुए बिलासपुर तक जाएगी। इस ट्रेन में बालोद के 137, बलौदाबाजार के 101, बिलासपुर के 67, धमतरी के 6, दुर्ग के 23, गरियाबंद के 21, जांजगीर-चांपा जिले के 54, कबीरधाम के 170, कांकेर 56, कोण्डगांव के 131, कोरबा के 97, मुंगेली के 25, रायपुर के 72, बस्तर के 380, बेमेतरा के 44,रायगढ़ के 48 और राजनांदगांव के 49 श्रमिक शामिल हैं।

जब श्रमिक भाई-बहन भूखे-प्यासे बेहाल होकर सड़कों पर हों तो हमें नींद कैसे आ सकती है : मंत्री डहरिया

पूर्व सीएम डा. रमन सिंह के बयान पर किया पलटवार

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए प्रदेश के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जब हमारे अपने श्रमिक भाई-बहन हज़ारों मील दूर भूखे-प्यासे बिना विश्राम किए सड़कों पर हों तो हमें नींद कैसे आ सकती है?

मजदूरों के पैरों पर छाले पड़ने के बयान पर डा. रमन सिंह के बयान पर प्रदेश के श्रम मंत्री डा. शिव डहरिया ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आश्चर्य हुआ है कि जिन लोगों को शर्मिंदा होना

चाहिए, जिन लोगों को श्रमिकों से माफी मांगनी चाहिए वे लोग दूसरों से पूछ रहे हैं कि उन्हें नींद आती है या नहीं? श्रम मंत्री शिव डहरिया ने डा. रमन सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि इस परिस्थितियों में न तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नींद आ रही है और न ही मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को नींद आ रही है। जब हमारे श्रमिक साथी हजारों मील दूर से भूखे-प्यासे चलकर आ रहे हों, उनके सिर पर बोझ हो, तो हमें नींद कैसे आ सकती है? डा. डहरिया ने कहा कि इन श्रमिक भाई-बहनों, उनके वृद्ध माता पिता और छोटे छोटे बच्चों को सिर पर गठरी उठाए, जैसे तैसे साइकिल पर बैठे और ट्रकों पर किसी बेजान सामान की तरह लदे देखकर हम सबको शर्मिंदगी भी होती है। मन बेचैन होता है कि इन्हें किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए। श्रम मंत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बयान देते समय भूल गए कि देश के करोड़ों श्रमिक आज जो दुख, पीड़ा और कष्ट झेल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। अगर केंद्र सरकार ने बिना विचार किए लॉकडाउन न किया होता, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर लिया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती।

छग होकर जाने वाले श्रमिकों को भोजन, पानी और परिवहन की व्यवस्था से मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर रायपुर सहित सभी जिलों में श्रमिकों के लिए किए गए विशेष इंतजाम, श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का माना आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ से होकर अन्य राज्य जाने वाले श्रमिकों को पूरी मदद और सहायता दी जा रही है। अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा खाने-पीने, नाश्ता, सेनेजाइजर, मास्क आदि दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए वाहनों का इंतजाम भी किया जा रहा है। श्रमिकों को इन व्यवस्थाओं से उनके राज्यों तक पहुंचने में बहुत बड़ी मदद मिली है जिसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार भी जता रहे है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी रायपुर तथा स्वंय सेवी संस्थाओं के द्वारा राजधानी रायपुर के विभिन्न स्थानों पर इन श्रमिकों के लिए भोजन, नाश्ते और पेयजल का इंतजाम किया गया है। भोजन और स्वल्पाहार वितरण के लिए अलग से वितरण काउंटर भी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। इन्हें स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए मास्क का वितरण किया जा रहा है।

वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने मुख्यमंत्री जी को दिया धन्यवाद

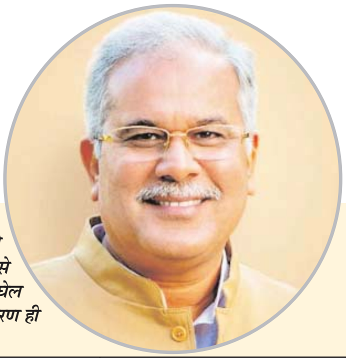

श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सोमवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है। कोरोना के कारण लॉक डाउन में गांधीनगर में परिवार सहित फंसे कोरबा के प्रदीप कुमार चैहान ने भावुक होते हुए कहा- 'लगता था कैसे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे..? कैसे घर वापसी होगी..? कोरोना के कारण खाने-पीने के भी लाले पड़ गये थे.. सेठ ने भी खाना देने और रखने से मना कर दिया था.. पत्नी के साथ दो बच्चों को लेकर घर लौटने की चिन्ता हर समय सताती रहती थी। भला हो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का.. मेरे परिवार सहित ऐसे कई परिवारों को छत्तीसगढ़ की धरती पर वापस लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की। ऐसे मुख्यमंत्री के कारण ही हम लोग आज रेलगाडी से बिलासपुर पहुंचे हैं। अपने छत्तीसगढ़ आ गये हैं, अब अपने घर जा सकेंगे।

कोरबा के प्रदीप कुमार चौहान ने भावुक होते हुए बताई अपनी कहानी

प्रदीप व उनके परिवार को लाने कोरबा कलेक्टर ने भेजी टीम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से आई इसी ट्रेन से कोरबा से हरदीबाजार से नौ किलोमीटर दूर नवाडीह गांव के निवासी प्रदीप कुमार चौहान अपनी पत्नी श्रीमती संतोषी बाई चैहान और दो छोटे बच्चों के साथ बिलासपुर पहुंच गये हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने इस परिवार को कोरबा लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष दल बिलासपुर भेजा है। आज शाम तक प्रदीप कुमार अपने परिवार के साथ कोरबा पहुंच जायेंगे। जहां उन्हें आगामी 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जायेगा।

दो ट्रेनों से लौटे 1991 मजदूर

अहमदाबाद के साबरमती और सिकदराबाद के समीप लिगमपल्ली से दो ट्रेनों में करीब कुल 1991 मजदूर बिलासपुर रेल्वे स्टेशन पहुँचे थे। जिसमे जिले के 1050 और अन्य जिलों के 941 मजदूर शामिल है। अन्य राज्यों से करीब 1050 मजदूर वापस लौटे है जिसमें-

- विकासखण्ड बिल्हा के 94,
- कोटा के 96,
- मस्तूरी के 800,
- तखतपुर के 44
- बिलासपुर क्षेत्र के 16

गुजरात और तेलंगाना से लौटे 275 श्रमिक का मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नेगिटिव

925 यात्रियों को लेकर पहुंची राजधानी

राजधानी एक्सप्रेस से पहुंचे 925 यात्रियों को लेकर पहुंची, यात्रियों को स्टेशन में ही स्क्रीनिंग कर उन्हें घर क्वारंटाइन किया जाएगा।

श्रमिकों ने ली चैन की सांस

प्रदीप कुमार की तरह कुछ अन्य लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया । अहमदाबाद से चली विशेष श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी आज सुबह लगभग पौने दस बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची तो इसमें सवार ग्यारह सौ से अधिक श्रमिकों ने चैन की सांस ली और अपने राज्य पहुंचने पर उनके मन मस्तिष्क में संतोष का भाव साफदेखा जा सकता था।

पता चलते ही कराया पंजीयन

उन्होंने बताया कि ऐसे में पता चला कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की है। प्रदीप कुमार ने अपने परिवार का पूरा विवरण स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराकर पंजीयन कराया और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लेकर आने वाली पहली गाड़ी से वे बिलासपुर पहुंच गये। प्रदीप कुमार ने कोरोना के इस माहौल में भी घर से दूर दूसरे राज्य में बिना काम के भूख-प्यास से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हे वापस लाने के लिए ट्रेन भेजने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बार-बार आभार और धन्यवाद जताया।

दीपावली के बाद गांधीनगर कमाने-खाने गया था प्रदीप का परिवार

दूरभाष पर बात करने पर प्रदीप कुमार चैहान ने बताया कि पिछले साल दीपावली के बाद वे अपने परिवार के साथ गांधीनगर कमाने-खाने पहुंचे थे। अपनी पत्नी और पांच साल तथा ढाई साल की दो बेटियों को साथ लेकर वे गांधीनगर के पास के गांव में ईंट भट्ठा में ईंट बनाने का काम करते थे। प्रदीप कुमार चैहान ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉक डाउन से ईंट भट्ठे का व्यवसाय बंद हो गया। कुछ दिन तक सेठ ने बैठाकर खिलाया परंतु बाद में उसने भी हाथ खड़े कर दिये। कमाई की रकम भी खतम होने की कगार पर है। ऐसे में लॉक डाउन की सख्ती के कारण जरूरी सामान लेने के लिए भी नहीं निकल पा रहे थे। जल्दी से जल्दी वापस घर लौटने की चिन्ता थी।

उत्तर प्रदेश से 1200 मजदूरों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन

- 800 मजदूर बेमेतरा
- 359 कबीरधाम
- 41 बलौदाबाजार भाटापारा

मुख्यमंत्री की पहल पर 3 लाख से अधिक श्रमिकों को पहुंचाई गई राहत

- अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ 2 लाख 20 हजार श्रमिकों एवं अन्य लोगों को वापस लाने का सिलसिला जारी
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लिंक के जरिए 2 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीयन
- अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के 32 हजार 11 श्रमिकों की हुई सकुशल वापसी
- छत्तीसगढ़ से लगभग 32 हजार 422 श्रमिकों को भेजा गया उनके गृह राज्य
- राज्य के 5 हजार 692 श्रमिकों की हुई गृह जिलों में वापसी
- अन्य प्रदशों में फंसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने बारह से तेरह मई तक 21 ट्रेनें
- शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 94,015 श्रमिकों को पुनः रोजगार
- अब तक छोटे-बड़े 1234 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ
- कारखानों के प्रबंधकों-नियोजकों से समन्वय कर 26,102 श्रमिकों को लगभग 34.62 करोड़ का भुगतान

संपादकीय

क्या कभी खत्म नहीं होगा कोरोना?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा इसका मतलब साफहै कि हमे कोरोना के साथ ही जीना होगा। कोरोना की वैक्सीन बनने की संभावना भी नगण्य है। यद्यपि विश्व के तमात देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के काम में लगे हुए है लेकिन इसमें किसे कब तक सफ्लता मिलेगी कह पाना मुहाल है। इधर पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम बदस्तूर जारी है। भारत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,000 से अधिक हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से डर कर आखिर कब तक लोग सारे काम धंधे बंद रख सकते है। अब हमे कोरोना के संग ही जीना होगा, सुरक्षित रह कर अपने काम पर लगना होगा। लॉकडाउन भी बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने जो कुठाराघात किया है उससे उबरने में लंबा समय लगेगा। जहां तक बात भारत की है तो यहां लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट दी जा रही है। लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाया जाएगा जो नए रूप में सामने आएगा। इस लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पहले के मुकाबले और ज्यादा छूट दिए जाने की संभावना है। ऐसा करना आवश्यक भी है। लगभग दो माह से अर्थिक गतिविधियों के ठप होने के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और करोड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस लिए अब आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है ताकि देश इस संकट से उबर सकें, किन्तु काम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतनी भी जरूरी है। क्यो कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बीस लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है उससे आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार को जो काम करना है वह कर रही है अब नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतें और इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का इमानदारी से पालन करें। कोरोना से लड़ना भी होगा और अपना करना भी होगा। यह तभी संभव है जब हम लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी दिनचरिया में बदलाव करें। खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों में और बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाएं सामाजिक दूरी बनाकर रखें तभी हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे।

विचार

तालाबंदी: उबाऊ भाषणों का दौर

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कल प्रधानमंत्री और आज वित्तमंत्री का भाषण सुना। दोनों भाषणों से आम जनता को जो उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री का भाषण सभी टीवी चैनलों पर रात को आठ बजे प्रसारित होगा, यह सूचना चैनलों पर इतनी बार दोहराई गई कि करोड़ों लोग बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से उसे सुनने बैठ गए लेकिन मुझे दर्जनों नेताओं ने फोन किए, उनमें भाजपाई भी शामिल हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण इतना उबाऊ और अप्रासंगिक था कि 20-25 मिनिट बाद उन्होंने उसे बंद करके अपना भोजन करना ज्यादा ठीक समझा लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आखिरी आठ-दस मिनिटों में उन्होंने काफी काम की बात कही। जैसे सरकार 20 लाख करोड़ रु. लगाकर लोगों को राहत पहुंचाएगी।

यह सब कैसे होगा, यह खुद बताने की बजाय, इसका बोझ उन्होंने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण पर डाल दिया। लोग प्रधानमंत्री से आशा कर रहे थे कि वे करोड़ों प्रवासी मजदूरों की घर-वापसी की लोमहर्षक करुण-कथा पर कुछ बोलेंगे और कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें कहेंगे, जिससे हमारे ठप्प कारखाने और उद्योगों में कुछ प्राण लौटेंगे लेकिन आज वित्तमंत्री ने लंबे-चौड़े आंकड़े पेश करके जो आर्थिक राहतों और सरल कर्जों की घोषणा की है, उनसे छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन जरुर मिलेगा लेकिन उन्होंने मूल समस्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि तालाबंदी से उत्पन्न बेरोजगारी, भुखमरी, मंदी, घनघोर सामाजिक और मानसिक थकान का इलाज क्या है ? दुनिया के अन्य देशों की सरकारें अपनी जनता को राहत कैसे पहुंचा रही हैं, यदि इसका अध्ययन हमारे प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री सरसरी तौर पर भी कर लेते तो उन्हें कई महत्वपूर्ण गुर मिल जाते। हमें विश्व-गुरु बनने का तो बड़ा शौक है लेकिन हम अपने नौकरशाही दड़बे में ही कैद रहना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि नेताओं की सबसे पहली चिंता उद्योगपतियों और व्यवसायियों से ही जुड़ी होती है, क्योंकि उनका सहयोग ही उनकी राजनीति की प्राणवायु होता है लेकिन वे लोग यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि शहरों में चल रहे उद्योग-धंधों की रीढ़ वे करोड़ों मजदूर हैं, जो हर कीमत पर अपने घरों पर लौट रहे हैं और जिनके वापस आए बिना उद्योग-धंधों के लिए दी गई ये आसान कर्जों की रियायतें निरर्थक सिद्ध हो जाएंगीं।

ज्ञान पाठ

18 मई को स्थिति 24 मार्च की स्थिति से भी बदतर होगी। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण हॉटस्पॉट्स के हमारे अस्पताल अत्यधिक प्रभावित होंगे। भारत ने हमेशा अधिक डॉक्टरों, नर्सों, अस्पतालों और दवाओं की सस्ती कीमतों पर मांग की, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मोदी और उनके फैन क्लब प्रदान किए गए समाधानों में कोई गलती देखने से इनकार करते हैं। वे राज्यों और लोगों को लॉक डाउन लागू नहीं करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज बहुत ही शानदार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। हालांकि, यह अपनी सुगंध के बिना गुलाब की तरह है। कोरोना के खतरे पहले से कहीं अधिक बढ़ रहे हैं, और पैकेज में सभी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक राशि नहीं है। सामाजिक दूरी की आवश्यकता, अनौपचारिक श्रमिकों के प्रवास और फंसे हुए लोग, और लोगों में भय मनोविकार ने देश की जनसांख्यिकी को पूरी तरह से बदल दिया है। वास्तविक आवश्यकता का कोई भी क्षेत्रवार आकलन नहीं किया गया है जो महान पैकेज की अस्पष्टता और खोखलापन को रेखांकित करता है।

मोदी पैकेज जमीनी स्तर पर निरर्थक है

डर और असुरक्षा, निराशा और अनिश्चितता की भावना के साथ भारत धीरे-धीरे खुल रहा है। 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज मिला है, जो खाली है। जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वे पैकेज में नहीं हैं। यहां तक कि वर्तमान पैकेज का वास्तविक मूल्य केवल 13 लाख करोड़ रुपये है। इसकी कीमत को बड़ा दिखाने के लिए हमने पहले के पैकेजों को जोड़ दिया है जो पहले ही हमारे लोगों, हमारी अर्थव्यवस्था को विफल कर चुके हैं। लॉकडाउन के तीन चरण 17 मई 2020 को समाप्त हो जाएंगे। 18 मई से चैथा चरण शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज से उनके फैन क्लब को काफी उम्मीदें हैं। लोग पैकेज की क्षमता के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। लोगों ने हमेशा उनके पहले के फैसलों के बारे में बड़ी बातें की थीं। वह हर चीज पर नाटक करते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं और हमारे देश में चल रही हर समस्या को मिटाने की कोशिश करते हैं। वह चुपचाप कुछ समय के लिए एक समस्या देखते हैं और फिर अचानक उच्च ध्वनि के साथ समाधान की बातें करते हैं। हालाँकि, समस्या और भी बदतर हो जाती है, और उसका समाधान एक नई समस्या बन जाता है। विमुद्रीकरण, किसान की आय को दोगुना करना, रोजगार और कौशल पैदा करना, इसके केवल कुछ उदाहरण हैं। वह अपने फैसलों में शानदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कुछ और ही होता है। भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के रूप में विमुद्रीकरण और काला धन बुरी तरह से विफल हो गये और अपने आप में एक संकट बन गये जबकि भ्रष्टाचार की स्थिति और भी बिगड़ गई जिसे हमने बैंक धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में देखा है। वह भारत को सबसे खराब वित्तीय गड़बड़ी और आर्थिक संकट को गहरा करने के लिए केवल समाधानों की एक श्रृंखला के साथ सामने आया।

हमारे प्रधानमंत्री ने घोंघे की गति के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हुए लगभग दो महीनों तक चुपचाप कोरोना की स्थिति देखी, और अचानक 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ बाहर निकले। यह अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में उनकी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए था। यह अब स्वीकार किया गया है कि उनके नेतृत्व में देश को कोरोना रोगियों को खोजने, ट्रैक करने और चलने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं किया गया था। उस समय कोरोना संक्रमण के मामले केवल 10 मौतों के साथ लगभग 500 थे और पिछले दिन 100 से कम नए मामले थे। अब भी, लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंत में, उनके नेतृत्व में भारत कोरोना संकट से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। लॉकडाउन के चैथे चरण की शुरुआत में, देश में संक्रमण के लगभग 100,000 मामले, 3000 मौतें, और रोजाना 4000 के आसपास नए मामले होने की संभावना है। लॉकडाउन को कोरोना संकट के समाधान के रूप में आगे लाया गया, जिसने डॉलर 4.64 बिलियन की दैनिक हानि के

> हमारे प्रधानमंत्री ने घोंघे की गति के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हुए लगभग दो महीनों तक चुपचाप कोरोना की स्थिति देखी, और अचानक 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ बाहर निकले। यह अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में उनकी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए था। यह अब स्वीकार किया गया है कि उनके नेतृत्व में देश को कोरोना रोगियों को खोजने, ट्रैक करने और चलने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं किया गया था।

साथ लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण ब्रेक लगा दिया है और 80 करोड़ लोग भुखमरी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। समाधान अपने आप में एक संकट बन गया है जबकि कोरोना संकट बिगड़ गया। 18 मई को स्थिति 24 मार्च की स्थिति से भी बदतर होगी। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण हॉटस्पॉट्स के हमारे अस्पताल अत्यधिक प्रभावित होंगे। भारत ने हमेशा अधिक डॉक्टरों, नर्सों, अस्पतालों और दवाओं की सस्ती कीमतों पर मांग की, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मोदी और उनके फैन क्लब प्रदान किए गए समाधानों में कोई गलती देखने से इनकार करते हैं। वे राज्यों और लोगों को लॉक डाउन लागू नहीं करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज बहुत ही शानदार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। हालांकि, यह अपनी सुगंध के बिना गुलाब की तरह है। कोरोना के खतरे पहले से कहीं अधिक बढ़ रहे हैं, और पैकेज में सभी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक राशि नहीं है। सामाजिक दूरी की आवश्यकता, अनौपचारिक श्रमिकों के प्रवास और फंसे हुए लोग, और लोगों में भय मनोविकार ने देश की जनसांख्यिकी को पूरी तरह से बदल दिया है। वास्तविक आवश्यकता का कोई भी क्षेत्रवार आकलन नहीं किया गया है जो महान पैकेज की अस्पष्टता और खोखलापन को रेखांकित करता है।

पैकेज में छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्योग खोलने के लिए हजारों करोड़ रुपये हैं, लेकिन यह पता लगाना भूल जाता है कि पर्याप्त संख्या में श्रमिकों पर अभी भी काम करना बाकी है। मोदी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है। उनके कार्यों का एक बड़ा हिस्सा अनुबंध श्रमिकों द्वारा किया जा रहा था। केवल कुछ ही श्रमिकों को नियमित और सुरक्षित नौकरियों में छोड़ दिया गया था। संविदा पर काम करने वाले पूरी तरह से नौकरी खो चुके हैं। स्थायी नौकरियों पर बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भी अपनी नौकरी खो दी है। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों ने लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल खो दिए हैं। उनमें से लाखों पहले ही अपने कामकाजी स्थानों को छोड़कर अपने घरों को चले गए। प्रश्न यह है कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के बिना कोई उद्योग कैसे पुनः आरंभ कर सकता है? पैकेज उद्योगों और व्यापार को पैसा देगा। और पैसा श्रमिकों के हाथ में नहीं जाएगा क्योंकि वे काम करने के लिए वहां नहीं हैं। रेलवे और परिवहन में अन्य ढील के कारण घर जाने वाले श्रमिकों में हाल ही में वृद्धि हुई है। वे उस समय जल्द ही लौटने की संभावना नहीं रखते हैं जब कोरोना तेजी से फैल रहा हो। श्रम उद्योग इस प्रकार पुनः आरंभ नहीं कर पाएंगे। इस परिदृश्य में, उद्योग स्वचालन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि वे श्रमिकों की कम संख्या के साथ काम कर सकें। यह श्रम बाजार में और गिरावट लाएगा। इसके अलावा, उद्योग और व्यवसाय मांग की कमी सहित कई कारणों से पूरी तरह से नहीं खुल सकते, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास पैसा नहीं है।

मोदी का पैकेज भूमि और श्रम के शोषण पर केंद्रित है ताकि आबादी की ऊपरी परतों को फायदा हो सके। राज्य श्रम कानूनों को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में धन नहीं हो सकता है और उन्हें आर्थिक दासता के करीब धकेल दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का आह्वान राष्ट्रीय स्तर के लिए है, न कि घरेलू स्तर के लिए। हमने खाद्यान्न के मामले में पहले ही अपना कुरूप चेहरा देखा है, जिसमें भारत राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर रहा है जबकि लाखों परिवारों के पास इसकी पर्याप्त मात्रा तक पहुंच नहीं है। आत्मनिर्भर भारत मिथ्या टर्म है। पैकेज को नई वास्तविकताओं के आधार पर फिर से काम करने की आवश्यकता है अन्यथा यह समाधान भी नए संकट लाएगा।

– (संवाद)

गांवो में बढ़े रोजगार के अवसर

रमेश सर्राफ

> कोरोना के कारण विदेशों में नौकरियां कर रहे लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के लौटने की स्थिति में उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाला समय दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत भारी रहेगा। जब कोरोना संक्रमण का दौर कम होगा तो बेरोजगारी का संकट मुंह बाये खड़ा होगा। अगर समय रहते अभी उसका निदान नही खोजा गया तो आने वाले समय में स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है।

भारत को कभी गांवो का देश कहा जाता था। देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवो में निवास करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांवो के खेतो और खलिहानो से होकर गुजरता है। मगर धीरे-धीरे समय ने करवट बदली। पिछले कुछ सालों से देश में शहरीकरण की रफ्तार तेज हुई है। लोग गांवो से निकलकर शहरों की तरफपलायन करने लगे। देखते ही देखते शहरों की आबादी बेहताशा ढंग से बढ़ने लगी। जीविकोपार्जन के चक्कर में लोग गांव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे। जहां ना तो उनके लिए ढंग से रहने की जगह थी ना ही सही ढंग का कोई रोजगार था। मगर शहरों की चकाचैंध से प्रभावित होकर गांव का युवा वर्ग तेजी से शहरों की ओर रुख करने लगा। गांव से लोगों के शहरों की तरफ पलायन से गांवो में रहने वाले लोगों का भी खेती में रुझान कम होने लगा। गांव की युवा पीढ़ी भी खेती से विमुख होकर शहरों की ओर दौड़ने लगी। मगर अचानक ही आए कोरोना संकट ने शहरों की ओर बेहताश दौड़ रहे लोगों को एक बार फिर से गांवों में आने को मजबूर कर दिया। गांव से शहरों में रोजगार के लिए गए सभी लोग इस वक्त यही प्रयास कर रहें है कि कैसे भी करके अपने गांव में अपने घर पहुंचा जाए। साधन नहीं मिलने से लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े हैं। शहरों में रह रहे लोगों को यकायक ही वर्षों पूर्व छोड़ा अपने गांव और घर याद आने लगे हैं। आज देश में शहरों से गांव की ओर तेजी से उल्टा पलायन हो रहा है। जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमने गांव को छोड़कर शहरों की तरफजाने कि जो प्रवृत्ति बनाई थी वह सही नहीं थी।

हालांकि लोगों को मजबूरी में गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाना पड़ा था। लगातार पड़ रहे अकाल, अतिवृष्टि के कारण खेती में गुजर-बसर करने लायक आमदनी नहीं हो पा रही थी। वही गांव के आसपास रोजगार के कोई कल कारखाने या अन्य साधन भी नहीं थे। जहां काम कर लोग अपना पेट भर सके। इसलिए लोगों को मजबूरी में दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना पड़ रहा था। कोरोना संकट के चलते लाखों लोगों का अपने मूल गांव की तरफ लौटने का सिलसिला अनवरत जारी है। सरकार द्वारा भी दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों तक पहुंच पा रहे हैं। कोरोना संकट के कारण लंबे समय से चल रही तालाबंदी के दौरान सरकारों को भी यह सोचने को मजबूर कर दिया है की रोजगार के साधन कल कारखानो को यदि शहरों तक ही सीमित न रखकर उनका गांवो तक विस्तार किया जाए तो लोगों को अपने आसपास अपने ही प्रदेशों में ही रोजगार मिल सकेगा। जिससे उनको अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में फिर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो देश को इस तरह के पलायन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी देश में उद्योग धंधों के लिए अधिकतर कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है। ऐसे में यदि सरकार कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए उसी क्षेत्र में उससे संबंधित कल कारखाने व स्वरोजगार के अन्य साधन उपलब्ध करवा देवे तो लोगों को बेवजह दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। सरकार को खेती में भी नवाचार करना चाहिए। यूरोपियन देशों की तरह हमारे देश में भी वैज्ञानिक विधि से खेती करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसान को कम समय में अधिक फसल मिलने से उसकी आमदनी बढ़ेगी। जिससे खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। खेती में अच्छी आय होने से उन्हे रोजगार के लिए अन्यत्र नहीं भटकना पड़ेगा। खेती के साथ सरकार को पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। खेती के साथ पशुपालन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पशुपालन किसानो की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। इसके साथ ही सरकार को ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जिनके लिए कच्चा माल व दक्ष कारीगर स्थानीय स्तर पर ही आसानी से सुलभ हो सकते हैं। ऐसा करने से गांवो के लोगों का रोजगार के लिए शहरों की तरफपलायन तो रुकेगा ही साथ ही घर परिवार के सभी लोग मिलकर अपने घर में ही कुटीर उद्योग में काम करने लगेंगे जिससे पूरे परिवार के सदस्य घर बैठे पैसे कमा सकेगें।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ये फेसबुक पर पैसे

ये फेसबुक पर पैसे माँगने का बहुत प्रचलन चल गया ....मैं इनबॉक्स में कोई पैसा नहीं माँग रही इसलिए मेरे अकाउंट से ऐसा मेसेज आये तो इग्नोर करिये ....और किसी को दान देने की इक्षा हैं ही तो मैं आपकी इक्षा का अपमान नहीं कर सकती आप मुझसे बात करके यहीं दें दीजियेगा।

– सीमा राय द्विवेदी

शराब बिक्री का विरोध

शराब बिक्री का विरोध करने वाले दलों के नेताओ और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो भी गंगा जल अपने हाथ मे लेकर कभी भी शराब का सेवन नही करने की शपथ लेते हुए आंदोलन करे ताकि जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल सके।

– संत आर थवाईत

खास पाती

आओ बहस करें

आओ बहस करें। समस्या पर नहीं समाधान पर। क्योंकि लोग समस्या गिना रहे, समाधान नहीं बता रहे। ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया। पर करना क्या था कोई नहीं बता रहा। कोरोना वायरस से बचने लॉकडाउन नहीं करना था तो क्या करना था ? आपके हिसाब से इस काल में बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? मजदूर, गरीब परेशान हैं, इन्हें परेशानी से कैसे निकाले, कोरोना से लड़ते हुए ? अर्थव्यवस्था को सम्हालने बड़ी पैकेज की घोषणा की गई है। आपके हिसाब से और क्या करना था ? जो बेहतर होता। – संजीव गुप्ता

दर्द के घर में आज रहता हूँ

दर्द के घर में आज रहता हूँ अपनी किस्मत से रोज़ लड़ता हूँ ओढ़ना है , यही बिछौना भी रोज़ अशआर जो मैं कहता हूँ तेज़ मेरे क़लम में है लेकिन रोशनाई मैं बनके बहता हूँ अब क़लम हो रहा , क़लम का सर रोज़ो - शब मैं सलीब चढ़ता हूँ मुझको रोज़े - हिसाब है मालूम इसलिए तो मैं रोज़े रखता हूँ क्यूँ निवाले नहीं मुक़द्दर में मुफ़लिसी में ही हाथ मलता हूँ बख्शू दो रब मेरे गुनाहों को मैं दरूदो - सलाम पढ़ता हूँ तन पे 'ऐनुल' लिबास ज़ख्मों का रोज़ जीता हूँ , रोज़ मरता हूँ।

- 'ऐनुल' बरौलवी

नीरस नमी, सीलन लाकडाउन सूरज आने

नीरस नमी, सीलन लाकडाउन सूरज आने वाली खुशियों का इशारा लाकर रख दूं क्या चौखट पे, कुछ देर सूरज.....? कितनी सीलन भर गयी है अंदर..गरमाई के चंद कतरे नीरस नमी को शायद कुछ उष्म कर दे!

– निधि भार्गव मानवी

जब शिकायत ख़त्म हो जाये...

जब शिकायत ख़त्म हो जाये... हर शब्द स्वयं में मौन कर जाये.. हौसलों में कही अनजानी बात जुबां से निकल के फिर ठहर जाये... वक़्त का मंज़र आइनें की तरह देखो, समझो, बूझो कि इसतरह कोई तंज तुमपे आकर अड़ जाये.. धीरे से एक पल मुस्कुरा देना.. वक़्त का एक दौर तेरा.. वक़्त का एक दौर मेरा.. कुछ भी न खोया, कुछ भी न पाया एहसासो के घेरे में खुद को है पाया जीवन लेन-देन का सौदा नही... अस्तित्व से निखर जीवन में समाये। – नंदिता तनूजा

गलियों में संध्या को जब जब

गलियों में संध्या को जब -जब- धुंधले अंधियारे. निकले हैं ! हम गीतों में दीपक बन कर - तब - तब सारी रात जले हैं ! गीत - कल्पनाएं... स्पनीली , उनकी नीली आंखे गीली , गीत-कल्पनाओं संग हम भी - रोते -रोते... .साथ चले हैं ! गहरे -गहरे से , सागर पर - ठहरे हैं कितने ही बादल , मेरी आंखों के साहिल से - अश्कों के बादल पिघले हैं ! – अजय कुमार सिंह भदौरिया

एक पल में इक सदी का मज़ा

एक पल में इक सदी का मज़ा हमसे पूछिये। दो दिन की ज़िन्दगी का मज़ा हमसे पूछिये।। भूले हैं रफ़्ता-रफ़्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिये।। हँसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह। हँसिये मगर हँसी का मज़ा हमसे पूछिये।- कमलकांत डोंगरे

एक दिन आयेगा जब तुम

एक दिन आयेगा जब तुम, तुम नहीं रहोगे मैं भी मैं नहीं रहूंगी तब मिलेंगे हम तुम नये सिरे से प्रेम बुनेंगे प्रेम कहेंगे प्रेम लिखेंगे मैं महसूस करना चाहती हूं अपने माथे पर वो नर्म छुवन लौटाना चाहती हूं वक्त को अनन्त काल तक। - आभा चन्द्रा

QUIZ TIME

1) किस इतिहासकार ने 1857 में विद्रोह को 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' कहा है?

2) विधान परिषद् साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक कितने माह तक रोक सकती है?

3) 'वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए मरे' यह कथन किस कवि का है?

4) 'ओलम्पिक' शब्द 'ओलम्पस' से आया है, यह किसका नाम है?

5) 2019 मिस इंग्लैंड का ताज किसे पहनाया गया था?

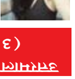

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) विनायक दामोदर सावरकर (2) चार माह तक (3) मैथिलीशरण गुप्त (4) पर्वत (5) भाषा मुखर्जी

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1606 - रूस में दो हजार विदेशी नागरिकों की हत्या हुई। 1875 - वेनेजुएला और कोलंबिया में भूकंप से 16 हजार लोगों की मौत हुई। 1881 - बर्लिन के पास लिस्टरफेलडर में बिजली से चलने वाली पहली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई। 1929 - हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में पहले ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। 1960 - भारत और इंग्लैड के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गयी। 1975 - सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। 1991 - महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनीं । 1996 - अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दसवें प्रधानमंत्री बने। 2007 - निकोलस सरकोजी फ्रांस के 23वें राष्ट्रपति बने।

मां की अंतिम इच्छा थी बेटी मुखग्नि देकर पिंडदान करें, बेटे ने मुक्ति धाम से अस्थियां चुरा लीं

■ **मां की अंतिम इच्छा के आगे रोड़ा बने बेटे के खिलाफ बेटी शिकायत लेकर पहुंची थाने**

नवप्रदेश संवाददाता

बिलासपुर । मां अंतिम इच्छा थी बेटी उसके मरण उपरांत मुखाग्नि दे और अस्थियां को विसर्जित करें बेटी ने मां की इच्छा अनुसार मुखाग्नि तो दे दी लेकिन अस्थियों के लिए विधायक और पुलिस का चक्कर काट रही है दरअसल मुक्ति धाम से बेटे ने बिना इजाज़त के की अस्थियों को ले आया है

व्यापार विहार क्षेत्र के 25 न. बंगला में रहने वाली शीला शुक्ला के साथ ही उनकी 90 वर्षीय बुजुर्ग मां रहती थी ।

पिछले करीब 30 सालों से शीला ही अपनी बुजुर्ग मां की पूरी तरह सेवा कर रही थी। अपनी बेटी के इसी सेवा और स्नेह से अभिभूत मां की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे मुखाग्नि देने का अधिकार भी बेटी शीला शुक्ला को ही मिले और अंत्येष्टि के बाद तर्पण पिंडदान और अस्थि प्रवाहित करने की जिम्मेदारी भी 90 साल की बुजुर्ग रितिका नर्मदा बाई मिश्रा ने अपनी बेटी शीला शुक्ला को ही सौंपा था। 13 मई को बुजुर्ग रितिका नर्मदा बाई मिश्रा का देहांत हो गया। मां की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए शीला शुक्ला ने भारतीय नगर श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया और मां की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए बेटी शीला शुक्ला ने हीं मुखाग्नि भी दी । लेकिन जब अगले दिन वह अपने बेटे के साथ भारतीय नगर स्थित श्मशान घाट माँ की अस्थियां समेटने पहुंची तो पता चला कि उनके पहुंचने से पहले ही उनका भाई चंद्रशेखर मिश्रा अपने बेटे शशांक शेखर मिश्रा के साथ पहुंचकर बिना गार्ड की अनुमति के ही जबरन मां की अस्थियां लेकर जा चुका है ।

मां के जीवित रहते चंद्रशेखर मिश्रा ने पुत्र होने का कर्तव्य कभी पूरा नहीं किया ।शायद मां को भी इसी बात का मलाल था तभी तो उन्होंने बाकायदा स्टांप पेपर में लिखकर और वीडियो बनाकर अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। अगर मां ने चंद्रशेखर को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं दिया तो फिर चंद्रशेखर का भी हक नहीं बनता कि मां की मृत्यु के पश्चात वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी अस्थियों को जबरन ले जाए । भाई द्वारा इस तरह अस्थियो की चोरी करने से भावनात्मक रूप से बुरी तरह आहत शीला शुक्ला ने शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंचकर अस्थि वापस देने की गुहार लगाई । पुलिस भी इस मामले में पशोपेश में नजर आ रही है । थाने में बात ना बनता देख शीला शुक्ला ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे का भी दरवाजा खटखटाया और उनसे मामले में दखल देते हुए अपनी मां के अस्थि कलश दिलाने की मांग की ,ताकि उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करते हुए उनके अस्थि फूल का विसर्जन पवित्र घाट में कर सके । शीला शुक्ला ने कहा कि मौजूदा स्थिति में वह इस कदर लाचार है कि अपनी मां की अंतिम इच्छा तक पूरी करने में भी समर्थ नहीं हो पा रही और इस राह में अड़चन कोई और नहीं उसका ही अपना सगा भाई है जिसने मां की कभी परवाह नहीं की। बिलासपुर विधायक ने भी पूरी मदद का भरोसा दिलाया है लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस और कानून बहुत कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा इस मामले में सामाजिक बैठक कर सुलह का रास्ता निकालना ही बेहतर उपाय है । जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब जरूर सिविल कोर्ट ने इस मामले को ले जाया जा सकता है।

न्यूज गैलरी

जिले में अब तक 465 श्रमिकों को वापस लाकर क्वारेंटाइन किया गया

कांकेर। प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा वापस लाने की अभियान चलाया गया, जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों से अब तक कांकेर जिले में 465 श्रमिकों को वापस लाया गया है तथा ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन किया गया है। कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने जिले के सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि क्वारेंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाकर भोजन, पेयजल, विद्युत, दवाईयां इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किये हैं। अंतागढ़ विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.के गुप्ता ने बताया कि 650 श्रमिकों में से 34 श्रमिकों को वापस लाकर क्वारेंटाइन किया गया है। इसी प्रकार कांकेर विकासखण्ड में 75, भानुप्रतापपुर में 50, कोयलीबेड़ा में 221, नरहरपुर में 32, चारामा में 18 और दुर्गूकोंदल में 35 श्रमिको को वापस लाया गया है तथा ग्राम पंचायतवार क्वारेंटाइन सेंटर बनाकर उन्हें आइसोलेट किया गया है।

दुकानों को अब शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति

कांकेर। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मई माह में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, लेकिन अत्यावशयक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि तक खुले रहेंगे।

स्टेशन में ठेकेदार वसूल रहा मनमानी शुल्क, तखतपुर विधायक ने रेलवे अधिकारी से की शिकायत

बिलासपुर । रेलवे स्टेशन की पार्किंग आकर जबरन वसूली और विवाद की खबर सुनाई पड़ती है। यहाँ आए दिन पार्किंग ठेकेदार रंगदारी दिखते हुए स्टेशन परिक्षेत्र अपना आतंक फैलाए हुए है. पर हद तो उस वक्त पार हो गई जब बिलासपुर रेल्वे स्टेशन में वाहन पार्किंग के ठेकेदारों द्वारा लॉक डाउन अवधि में भी फंसे वाहनों का किराया वसूला कर रहे थे. इस संकट के दौर में ठेकेदारों द्वारा लॉक डाउन के कारण फंसी वाहनों के मालिकों से डेढ माह का पार्किंग शुल्क वसूल किया जा रहा था, जो काफी अधिक था. जिसे चुका पाने में लोगों ने असमर्थता ज़ाहिर की पर पार्किंग ठेकेदार कहा मानने वाले थे.वही जब इस बात की जानकारी तखतपुर विधायिका रश्मि सिंह को लगी तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करते हुए लॉक डाउन अवधि के दौरान पार्किंग शुल्क नही लेने का आग्रह किया।

कोरोना वारियर्स बैंक, आज लॉकडाउन में भी सेवा देंगे

बिलासपुर । बैंकर्स क्लब बिलासपुर ने शनिवार को भी पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति में उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया है । इस सम्बंध में बैंकर्स क्लब बिलासपुर के संयोजक ललित अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने मई माह के प्रत्येक शनिवार व रविवार को कम्प्लीट लॉक डाउन का निर्णय लिया है।

मनरेगा में 2 लाख से अधिक श्रमिकों को मिल रहा है काम

सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला जिला है बिलासपुर

■ **लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा बना रोजगार का मुख्य साधन**

बिलासपुर । मनरेगा के तहत गांवों में 2 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। यह संख्या पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रोजी-रोटी की समस्या दूर हो गई।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन में लोगों को आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा से रोजगार सुलभ हो रहा है।

मनरेगा जिले में 02 फरवरी 2006 से लागू है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गत वर्षों में अधिकतम 1 लाख 20 हजार श्रमिकों के लिये रोजगारसृजन किया गया था। इस योजना में विगत 15 वर्षों में इतने श्रमिक कार्यरत नही थे जितने इस वर्ष लॉकडाउन की अवधि में कार्यरत हैं। यह जिले की बड़ी उपलब्धि है।

लॉकडाउन अवधि में ग्रामीणों एवं अन्य स्थानों से अपने गांव लौटकर आने वाले प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्य योजना माह विगत मार्च माह में ही तैयार कर ली गयी थी। सभी ग्राम पंचायतों के लिए 14537 कार्य 269.70 करोड़ लागत के स्वीकृत किये गए ताकि ग्रामीणों को गांव में ही तत्काल कार्य उपलब्ध हो सके।

गांवों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मनरेगा के अंतर्गत तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, भूमि सुधार, कूप निर्माण, पशु शेड निर्माण एवं वृक्षारोपण हेतु गड्ढे के खुदाई इत्यादि कार्य कराए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में योजना प्रारंभ से अब तक का सर्वाधिक रोजगार सृजन कर 2 लाख 3 हजार श्रमिक बिलासपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में संयुक्त रूप से नियोजित किये गए हैं।

वर्तमान में विकासखण्ड बिल्हा में 448 कार्य चल रहे हैं जिसमें 38940 मजदूर कार्यरत हैं। इसी प्रकार विकासखण्ड कोटा में 364 कार्यों में 35780 श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। विकासखण्ड तखतपुर में 350 कार्य चल रहे हैं यहां प्रतिदिन 41311 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। विकासखण्ड मस्तूरी में 529 कार्य संचालित हैं जिसमें 39191 मजदूरों को लाभ मिल रहा है। विकासखण्ड गौरेला में 314 कार्य चल रहे हैं जिसमें 9600 श्रमिक कार्यरत हैं। विकासखण्ड पेण्ड्रा में 283 कार्य संचालित हैं जिसमें 12680 मजदूर कार्य कर रहे हैं और विकासखण्ड मरवाही में 644 कार्य चल रहे हैं जिसमें 25960 मजदूर कार्य कर रहे हैं। कार्यस्थलों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हाथ धोने के लिये सेनेटाईजर की भी व्यवस्था प्रत्येक कार्यस्थल पर की गई है।

शाम 5 बजे तक खुलेगी दुकानें समय सीमा में 1 घंटे की बढ़ोतरी

■ **आज और कल जारी रहेगा पूर्ण लॉक डाउन**

बिलासपुर । लॉक डाउनलोड तीन में धीरे-धीरे राहत दी जा रही है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफसंकेत दिए हैं कि लॉक डाउन 4 भी 18 मई से आरंभ होगा लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि इसका रंग रूप नियम कायदे बिल्कुल अलग होंगे, जिसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं ।इससे पहले जहां देशभर में दुकानें सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक खुल रहे थे तो वही बिलासपुर में यह समय अवधि सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक ही थी, जिसमें आंशिक बढ़ोतरी करते हुए अब समय सीमा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की जा रही है। सुबह 7से 5 बजे तक वह सभी दुकानें खुलेगी जिन्हें पूर्व में भी खोलने के आदेश मिल चुके है । निर्माण ,उद्योग शासकीय निजी कार्यालय समेत उचित मूल्य की दुकान , गैस एजेंसी हॉस्पिटल ढाबे रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप दवाई दुकान , मिल्क पार्लर को पहले भी छूट मिली हुई थी ,उन्हें शहर छोड़ कर शेष व्यवसाय अब शाम 5 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे

जबकि स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थल आदि पहले की तरह ही बंद रहेंगे। लेकिन इसी दौरान प्रत्येक शुक्रवार रात 7:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण बाजार दुकाने पहले की तरह ही बंद रहेंगे यानी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉक डाउन जारी रहेगा । लेकिन उस दौरान भी प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठान और सेवाओं को पहले की तरह ही छूट हासिल होगी।

विधायक पांडे की अपील पर संपत्ति कर जमा करने की बढ़ाई गई तिथि

■ **मंत्री शिव डहरिया और विभागीय सचिव से चर्चा कर विधायक ने तिथि बढ़ाने की मांग की थी**

बिलासपुर । कोरोनावायरस की वजह से देशभर में जारी लॉक डाउन के कारण अधिकांश कामकाज बंद है और लोगों के आय के स्रोत ठहर गए हैं। ऐसे में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि गुजर जाने से लोग पशोपेश में है । सामान्यतः वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च नगर निगम सीमा में संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि होती है लेकिन इस वर्ष विशेष परिस्थिति होने के कारण इसे बढ़ाकर पहले 30 अप्रैल और फिर 15 मई तक कर दिया गया था , लेकिन कोरोनावायरस का संकट अभी टला नहीं है और देशभर के साथ बिलासपुर में भी लॉक डाउन जारी है। ऐसे में शुक्रवार 15 मई को संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि होने से लोगों में इसे लेकर आशंका है कि निर्धारित तिथि तक संपत्ति करना जमा न करने पर जुर्माना और अन्य तरह की कार्यवाही हो सकती है ।

इस मुद्दे को भांपते हुए बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने नगरीय प्रशासन मंत्री और नगरी प्रशासन विभाग के सचिव से चर्चा कर संपत्ति कर जमा करने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की । कोरोना वायरस के कारण लगभग सभी वर्ग प्रभावित हुआ है । चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यापारी या सेवा कर्मी। जिस कारण से इस वर्ष संपत्ति कर पटाना आसान नहीं हो रहा। मकान दुकान का संपत्ति कर नहीं जमा करने वालों के लिए अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित थी लेकिन इस तिथि तक भी अधिकांश लोग संपत्ति कर जमा नहीं कर पाए। इसलिए विधायक शैलेश पांडे ने संपत्ति कर जमा करने की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डेहरिया और विभाग के सचिव अलरमेलमंगई डी से चर्चा कर संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की कोशिशें रंग लाई और नगरी प्रशासन विभाग ने संपत्ति कर जमा करने की तिथि में 15 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए अब इसे 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है ।

टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी पूछेगा आपका पता, ताकि आसानी से ट्रेस कर सके

बिलासपुर । रेलवे ने ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग में बदलाव किया है लॉकडाउन के बीच अगर आप विशेष ट्रेन से घर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट बुक कराते हुए एक और जानकारी देनी होगी. अब सभी रेलवे यात्रियों को अपने गंतव्य का पूरा पता देना होगा. यानी टिकट बुक करते समय आपको बताना होगा आप किस पते पर जा रहे हैं. यह इसलिए किया गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो आसानी से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो सके. यह 13 मई से शुरू किया गया है. वहीं, दूसरी ओर भारतीय रेल ने सामान्य यात्री ट्रेनों में 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक सभी टिकटों को रद्द कर दिया है, इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और उपनगरीय सेवाएं भी शामिल हैं. सभी यात्रियों को पूरा किराया रिफंड कर दिया जाएगा. रेलवे ने गुरुवार को बयान में यह जानकारी दी , हालांकि रेलवे ने कहा कि इस दौरान, प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रहीं 'श्रमिक' ट्रेनें और नई दिल्ली तथा प्रमुख स्टेशनों के बीच चल रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा।

देश में अगर कोरोनावायरस की स्थिति की बात करें तो गुरुवार को कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 78,003 पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से अब तक 2549 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मरीज़ मिले हैं और 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कोरोना को अब तक 26,235 मरीज़ मात दे चुके हैं. रिकवरी रेट सुधर कर 33.63 प्रतिशत हो गया है. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि इससे पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग टिकट की शुरुआत करने की घोषणा की थी। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को न केवल अपनी वर्तमान विशेष ट्रेनों, बल्कि आगामी सभी ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान शुरू करने संबंधी आदेश जारी किया. वर्तमान विशेष ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट बुक किये जा रहे हैं, वहीं 22 मई से शुरू हो रही यात्राओं के लिए 15 मई से टिकटों की बुकिंग में प्रतीक्षा सूची में टिकट बुक कराने का प्रावधान होगा। अब 1 एसी में 20, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, 2एसी में 50, 3एसी में 100, एसी चेयर कार में 100 और स्लिपर में 200 तक वेटिंग टिकट काटे जाएंगे

नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में शिफ्ट हुआ बुधवारी बाजार, पूर्ण लॉकडाउन में भी कर सकेंगे खरीदी लोग

बिलासपुर । फिर से नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट मैदान में शिफ्ट हुआ बुधवारी का सब्जी बाजार , इससे पहले इसे उर्दू स्कूल मैदान में किया गया था शिफ्ट, शनिवार रविवार को भी बाजार खुला रहेगा।

एक बार फिर से रेलवे क्षेत्र के सब्जी बाजार को नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से पहले बुधवारी में लगने वाले सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने पर इसे रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट खेल मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था लेकिन जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू हुई और उसी मार्ग से बसों की आवाजाही की जाने लगी तो एहतियात के तौर पर इस बाजार को कंस्ट्रक्शन कॉलोनी उर्दू स्कूल मैदान में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। अब एक बार फिर से स्थिति सामान्य होने पर सब्जी बाजार को फिर से रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट मैदान में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही बुधवारी बाजार के भीतर के उन दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है जो छूट के दायरे में शामिल है। हालांकि अब भी बुधवारी बाजार मार्ग मुख्य मार्ग की दुकानें पूर्व की तरह ही बंद रखी गई है ताकि सड़क पर बेवजह की भीड़ जमा ना हो और बसों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो । एक बार फिर से रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट मैदान में सब्जी बाजार के शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को चहल-पहल नजर आई। बाजार का समय अलबत्ता अब बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है लेकिन फिर भी तेज धूप के कारण खरीदार और विक्रेता दोनों सुबह-सुबह ही खरीदी बिक्री को महत्व दे रहे हैं। अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉक डाउन के दौरान भी रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट मैदान का सब्जी बाजार खुला रहेगा हालांकि यह शाम 5:00 बजे तक नहीं बल्कि दोपहर 12:00 बजे तक ही खुलेगा। इसे देखते हुए शुक्रवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि बार-बार बाजार को इधर से उधर किए जाने से उन्हें दिक्कत हो रही है और सब्जी विक्रेता भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इस तरह के कदम बेहद जरूरी है और लोग भी अब धीरे-धीरे इसके आदी होते जा रहे हैं।

न्यूज गैलरी

साइन बोर्ड से टकराई बाइक, एक मृत

महासमुंद। नेशनल हाईवे पर लगे साइन बोर्ड में टकराने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं पीछे सवार एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र का है। घटना 12 मई शाम चार बजे की है। युवक तेज एवं लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाते हुए साइन बोर्ड को टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई निवासी सोनूराम ध्रुव पिता आनंदराम (28) संतूराम के साथ बाइक-सीजी 06 जीजे 6017 से शाम चार बजे वापस घर वापस जा रहा था। एनएच-353 विश्वा ढाबा के पास बाइक रोड किनारे लगे साइन बोर्ड से टकरा गया। इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई।

कोतवाली प्रभारी समेत तीन निलंबित

महासमुंद। कोतवाली के मालखाना से सात पेटी शराब कम पाए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कोतवाली प्रभारी राकेश खुंटेश्वर सहित माल मुंशी अनिल साहू व माल मददगार पुनीत पटेल को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। शराब गायब होने के मामले में एएसपी मेघा टेंभुरकर थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक व आरक्षक से पूछताछ कर रहीं हैं, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। वहीं विभागीय सूत्रों की मानें तो लॉकडाउन के दौरान सरकारी शराब दुकान बंद होने के कारण कोतवाली के मालखाने में रखी गई जब्त शराब को पुलिसकर्मियों द्वारा पीने और बेचे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर का कहना है कि जब्त की गई शराब के गायब होने की शिकायत लगातार मिल रही थी। बुधवार को कोतवाली थाना के मालखाना का औचक निरीक्षण किया गया। रिकॉर्ड देखने से पता चला कि मालखाने में वर्ष 2019 में एवं 2020 में अवैध शराब तस्करी व बिक्री के 17 प्रकरण दर्ज कर 25 पेटी शराब जब्त किए थे, जिसमें से 7 पेटी कम पाई गई।

डीजीपी ने किया एसडीओपी कार्यालय का लोकार्पण

महासमुंद। बागबाहरा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय एवं निवास का लोकार्पण मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने गुरूवार को किया। विशिष्ट अतिथि पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज डॉ आनंद छाबड़ा रहे। पूजा-पाठ के साथ पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने फीता काटकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यालय परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने ने बागबाहरा थाना पहुंच पुलिस बालमित्र उद्यान और ओपन जीम का लोकार्पण किया। पत्रकारों से चर्चा में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोरोना संकट में पुलिस केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित रखने जुटी है। एक सवाल के जवाब में श्री अवस्थी ने कहा कि गांजे की तस्करी ओड़िशा से बागबाहरा व सरायपाली रास्ते होती है, इसके लिए गांजा के सप्लाई के ठिकानों तक पुलिसिया कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, एएसपी मेघा टेम्भुलकर, प्रशिक्षु आईपीएस आंजनेय, एसडीओपी लितेश सिंह समेत थाना स्टॉफमौजूद रहा।

युवक से मारपीट

महासमुंद। कुम्हारपारा में आटा चक्की के पास तीन युवकों ने मोहल्ले के युवक की पिटाई कर दी। पुलस्य सिंह चंद्राकर के मुताबिक बुधवार शाम पौने 7 बजे वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी आरोपी महेश साहू और उसके दो दोस्तों ने उसे बाइक से गिरा दिया। विरोध करने पर उक्त युवकों ने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।

युवकों में मारपीट

महासमुंद। सरायपाली के अटल आवास में बुधवार दोपहर 12 बजे घर आने-जाने की बात पर दो युवकों में मारपीट हो गई। जिसमें राजेंद्र नागवंशी ने विजय कुमार गुप्ता की पिटाई कर दी। पुलिस ने शिकायत पर राजेंद्र के खिलाफधारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।

लॉकडाउन का उल्लंघन, कार्रवाई

महासमुंद। नियत समय से अधिक समय तक दुकान खोलने पर पुलिस ने जूता दुकान के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के पास जूता-चप्पल की दुकान खुली थी जहां ग्राहकों को नियत समय के बाद भी सामान बेचा जा रहा था। जिस पर वार्ड 11 निवासी सैयद अब्दुल मजीद के खिलाफधारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पौने छह लीटर शराब बरामद

महासमुंद। पिटियाझर नहर के पास पुलिस ने बाइक सवार युवक के कब्जे से देशी एवं अंग्रेजी शराब बरामद की। बुधवार अपरान्ह 4 बजे बाइक क्रमांक सीजी 06 जीबी 9420 सवार जिवतरा निवासी किरण पिता गोकूल साहू से 5.760 लीटर देशी प्लेन/ अंग्रेजी शराब बरामद की। जिस पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

जहर गटक कर अधेड़ ने दी जान

महासमुंद। कौंदकेरा के दादरखार में बुधवार को गांव के नंदलाल पिता सोरथ साहू (50) ने जहर सेवन कर ली। उन्हे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।

कोरोना महामारी नियंत्रण के संबंध में जागरुकता अभियान

महासमुंद। विकासखंड पिथौरा के ग्राम सांकरा में कोरोना महामारी नियंत्रण के संबंध में जागरुकता अभियान को लेकर नवजीवन सखी सखा और प्रेरक को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इससे निपटने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। व्यक्तिगत साफ-सफाई, सोशियल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर का उपयोग, मास्क पहनने, घर में सुरक्षित रहने, गर्मी के समय धूप से बचने के लिए सूती कपड़े को ढंककर चलने के लिए प्रेरित किया गया।

मनरेगा के कार्यों में सरकारी धन की जमकर बंदरबांट!

- निर्धारित पैमाने पर मिट्टी खुदाई नहीं, बावजूद पूरा भुगतान

नवप्रदेश संवाददाता

महासमुंद। मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में शासकीय राशि की जमकर बंदरबांट की जा रही है। अनेक जगह से शिकायतें मिल रही है कि रोजगार सहायक, पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से अनियमितता बरती जा रही है। मजदूर भी निर्धारित पैमाने पर मिट्टी खुदाई न कर पूरी राशि ले रहे हैं। मनरेगा अधिनियम में 12म12म12 = 144 फीट मिट्टी खोद कर फेंकने पर जोड़े को 380 रुपए भुगतान किया जाना है पर वर्तमान में कई जगह बमुश्किल से 70 फीट मिट्टी फेंकने पर 380 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। गोदी की खुदाई निर्धारित पैमाने पर नहीं हो रही है। औसतन 4 ईंच तक ही गोदी खोदी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे जिले क्षेत्र के मनरेगा काम में जमकर धांधली की जा रही है। कार्य देखने कोई भी अधिकारी मैदान में नहीं जाते इसलिए मैदानी कर्मचारी और ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अनेक जगह बिना काम कराए फर्जी बिल लगाकर राशि अहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत होने के बाद भी कोई जांच नहीं की जाती और न ही दोषियों के खिलाफकोई कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही एक मामले का खुलासा 'छत्तीसगढ़ जनादेश' ने किया था कि पूर्व ग्राम सुखरीडबरी में निर्मलाघाट निर्माण किए बिना सचिव राशि आहरण कर लिया था। सोशल आडिट से इस फर्जी और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था।

भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा रैकेट!

उल्लेखनीय है कि रोजाना फर्जी नाम से मस्टररोल भरकर हजारों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है लेकिन कभी इस भुगतान का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता। बताते हैं कि ग्राम पंचायतों के सचिव को बिना विश्वास में लिए रोजगार सहायकों को इस योजना का सर्वेसर्वा बना दिए जाने से भ्रष्टाचार का ग्राफबढ़ा है। अनेक ऐसे जॉब कार्डधारक हैं जो मनरेगा में कभी काम नहीं करते उनके जॉब कार्ड को निरस्त किया जाना चाहिए मगर निरस्त नहीं किए जाने के कारण उसी जॉब कार्ड में फर्जी मजदूरी चढ़ाकर भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। मनरेगा के कार्यों का मूल्यांकन कराए जाने से गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के सारे मामले उजागर हो जाएंगे। इस योजना में एक रैकेट भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है।

काम कराने वाले मुफ्त में हजारों रुपए खा रहे, हम मजदूर तो 2-3 घंटे मिट्टी फेंक कर राशि ले रहे: बताया गया है कि बागबाहरा, पिथौरा क्षेत्र में स्वीकृत कार्य का कहीं सूचना फ्लक नहीं है और मजदूरों द्वारा खोदे गए गड्ढे 2-4 इंच ही है। कहीं भी 7-8 इंच गोदी गड्ढे नहीं हैं। एक मजदूर से जब पूछा गया कि गोदी इतना कम क्यों खोदा जा रहा है? तो उसने कहा- साहब, काम कराने वाले ही मुफ्त में हजारों रुपए खा रहे हैं इसलिए ये हाल हुआ है। हम मजदूर तो कम से कम 2-3 घंटे मिट्टी फेंक कर राशि ले रहे हैं।

भुगतान से पहले सत्यापन कराने की जरूरत: पंचायतों में 10-20 लाख रुपए की लागत से कराया गया तालाब निर्माण खेत नजर आ रहा है। बागबाहरा में पांच एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर तालाब निर्माण के लिए 19.76 लाख रुपए की स्वीकृति मार्च 2018 में दी गई थी लेकिन दो साल बाद तालाब का क्षेत्रफल बमुश्किल करीब दो एकड़ के आसपास ही होगा। बहरहाल, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने हेतु मनरेगा के तमाम कार्यों का भुगतान से पहले सत्यापन कराई जाए तो निश्चित ही इस योजना में हो रहे बंदरबांट और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

मजदूरों को अब तक भुगतान नहीं

यही नहीं मनरेगा शाखा के एक कम्प्यूटर ऑपरेटर ने मजदूरों तथा निर्माण कार्य की राशि अपने तथा परिजन के पंजाब बैंक के खाता में अंतरण कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही मजदूरों को अब तक भुगतान कराया गया है।

श्रमिक पहुंचे अपने छत्तीसगढ़ कहा-सब कुशल मंगल

- मुख्यमंत्री के प्रति श्रमिकों ने कृतज्ञता जाहिर की
- छत्तीसगढ़ आने पर छलका उल्लास

राजनांदगांव। विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) से आने वाली ट्रेन से श्रमिक उतरे तब उनके चेहरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचने की खुशी एवं राहत दिखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में कोविड़-19 के कारण लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राजनांदगांव वापसी संभव हो सकी। बड़ी संख्या में राजनांदगांव जिले के 24 एवं कबीरधाम जिले के 56 श्रमिक पहुंचे। रेल्वे स्टेशन में ही आए हुए कबीरधाम जिले के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण रैन बसेरा में किया गया।

विजयवाड़ा से आए रमेश ने बताया कि वे अपनी पत्नी मीना एवं अपने बच्चे के साथ रोजी मजदूरी के लिए विजयवाड़ा गए थे और लॉकडाउन में फंस गए थे। वहां से अपने घर आना चाहते थे और इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर कैसे पहुंचे। इसी समय श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जानकारी मिली और हम यहां आ गए। अब सब कुशल मंगल है। हम अपने गांव चले जाएंगे इसी बात की बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री बघेल के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारा विशेष ध्यान रखा, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार विश्वकर्मा बताया कि 4-5 माह पहले रोजी मजदूरी के लिए विजयवाड़ा गए थे। उनकी बातों से छत्तीसगढ़ वापस आने का उल्लास झलक रहा था। उन्होंने शासन को छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीमती दुर्गा ने कहा कि बहुत दिन से घर से बाहर थे और लॉकडाउन में फंस गए थे। घर की बहुत याद आ रही थी। अब अपने घर पंडरिया जिला कबीरधाम पहुंच जाएंगे। मनोज एवं श्रीमती सीमा साहू विजयवाड़ा में लॉकडाउन में फंस गए थे। घर वापस आने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली और हम अपने घर पंडरिया पहुंच जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, रेल्वे पुलिस फोर्स उपस्थित थे।

40 लाख की ठगी का पार्टनर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी थाने में सुसाइड नोट छोड़कर फरार

नवप्रदेश संवाददाता

राजनांदगांव। टाइपिंग कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर 127 लोगों से 40 लाख 76 हजार पांच सौ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि कलेक्टोरेट के लोक सेवा केंद्र में काम करने वाले दो युवक हैं, जिनके खिलाफ प्रार्थी बरबसपुर घुमका निवासी देवेश पिता ललित वर्मा ने बसंतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर मुख्य आरोपी स्टेशन पारा राजनांदगांव निवासी आकाश पिता लल्लू यादव और उसके पार्टनर गौरी नगर निवासी 27 वर्षीय शाहरूख पिता शहनवाज खान के खिलाफ धारा 420 व 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पार्टनर शाहरूख खान को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल तक भेज दिया है। इधर मुख्य आरोपी आकाश यादव फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आकाश ने दो दिन पहले चिखली चौकी में सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसके बाद से वो फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है।

प्रार्थी देवेश वर्मा ने बताया कि बीते वर्ष मेरी दोस्त दीप्ती शर्मा के माध्यम से आरोपी आकाश यादव से उसकी पहचान हुई थी। आकाश ने प्रार्थी को टाइपिंग कंपनी के बारे में बताया और उसमें काम दिलाने की बात कही। इसके लिए आरोपी ने मुझे अपने साथ तीन लोगों को जोड़ने के लिए कहा। सभी लोगों से सिक्युरिटी के रूप में 18 हजार रुपये जमा कराया। आरोपी ने फौव्वारा चौक स्थित काम्प्लेक्स में आफिस भी खोला, जहां मेरे साथ 33 लोगों को काम पर रखा। हर माह 12 हजार रुपये वेतन की बात कही, लेकिन एक भी महीने वेतन नहीं दिया। वेतन की बात कही तो आरोपी ने अपनी मां के साथ बैठक कराकर दिल्ली से पैसे आते ही वेतन देने की बात कही। इसके बाद से आकाश मोबाइल बंद कर गायब हो गया है। काम्प्लेक्स में खोला गया कार्यालय भी बंद कर दिया है। इसको लेकर सभी लोग पैसों के लिए भटक रहे हैं। पुलिस से शिकायत कर प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफकड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की। जिसमें यह बात भी सामने आयी कि आरोपित आकाश यादव ने दो दिन पहले ही चिखली चौकी में सुसाइड नोट छोड़ा है। पुलिस मामले में गुम इंसान दर्ज कर उसकी खोजबीन कर रही है। प्रार्थी ने शिकायत में यह भी बताया कि आरोपित ने सिक्योरिटी अमाउंट के बदले टाइपिंग करने वालों को 9 हजार और नॉन टाइपिंग स्टाफ को छह हजार रूपये वेतन देने का आश्वासन दिया। सभी लोगों को कैंडिडेट जोड़कर चैनल बनाने कहा। प्रार्थी ने बताया कि करीब 9 लोग पहले जुड़े, जिनके माध्यम से 127 लोगों को जोड़कर सभी से सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई। इसे लेकर आरोपित फरार हो गया है।

अफवाहों पर न दें ध्यान नमक का पर्याप्त भंडारण

- नमक की कमी की अफवाह पर विधायक ने की अपील

महासमुंद। विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने क्षेत्र में नमक की कमी को लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में प्र्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की बिलकुल जरूरत नहीं है।

विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों से नमक की कमी को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है जिससे दुकानों में नमक खरीदने लोग पहुंच रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश में नमक की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लॉकडाउन घोषित हैं। इस स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। वर्तमान में जिले में नमक सहित अन्य सभी जरूरी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए सरलता से उपलब्ध हैं। विधायक श्री चंद्राकर ने इस संबंध में जिले के अफसरों से भी चर्चा की। जिस पर अधिकारियों ने विधायक श्री चंद्राकर को बताया कि जिले में शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली निःशुल्क नमक का भी वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नमक का भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिले में नमक की मासिक आवश्यकता दो हजार 689 क्विंटल है जबकि वर्तमान में नमक की उपलब्धता चार हजार 346 क्विंटल है। उन्होंने बताया कि जिले में दुकानों की जॉच करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

एपीएल हितग्राहियों को भी नमक की पात्रता

विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एपीएल राशन कार्ड के हितग्राहियों को नमक की पात्रता निर्धारित की है। इसके लिए उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए सामान्य राशनकार्ड धारकों को एक जून 2020 से दस रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित की है।

आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री : संतोष पाण्डेय

राजनांदगांव। कोरोना वायरस के संक्रमण व महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति देश के लिए समर्पण की भावना को नमन करते हुए सांसद संतोष पाण्डेय ने साधूवाद दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्पण को प्रेरणादायी बताते हुए कहा है कि भारत जैसे विकासशील, घनी आबादी और जागरूकता में कमी को देखते हुए पूरा विश्व भारत में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण के प्रति आशंकित था। ऐसे समय श्री मोदी व उनकी टीम ने बताया की सर्वमान्यता व नियंत्रण से कैसे बड़े से बड़े संकट से निपटा जा सकता है। मंगलवार को देश को संबोधन करते हुए श्री मोदी ने न सिर्फ गरीब, निम्न आय वर्ग व किसानो की चिंता की वरन उद्योगपतियों की भी चिंता करते हुए उन्हें राहत देकर संतुलन बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण और गुढ़ संदेश उनका देशवासियो के लिए है कि जब विदेशों के स्तरहीन सामग्री क्रय कर बहुमूल्य देशी मुद्रा का विदेश पलायन की प्रवित्ति को त्यागना है, जिससे उन्हें स्थानीय उत्पादन में बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरव स्वावलंबी बनने का आह्वाहन किया है। उद्योगपतियों को लोन पर मूलधन वापसी में 1 वर्ष की छुट, निम्न आय वर्ग को ईपीएफसे मुक्ति तथा मध्यम वर्ग के ईपीएफ में कटौती 12 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत, 6 महीने तक रेरा से तहत नियमों से रियल एस्टेट को राहत, टीडीएस व टीसीएस की दर में कटौती, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाने इस प्रकार से सभी वर्गों की चिंता करते हुए देश नहीं झुकने दूंगा स्तुति को चरितार्थ किया है।

संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने किया बाग नदी बॉर्डर का निरीक्षण

राजनांदगांव। संभागायुक्त जीआर चुरेन्द्र एवं पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बागनदी बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, एसडीएम अविनाश भोई एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बोडराभाठा जंगल के समीप पहुंचा हाथियों का दल

- आसपास के गांवों में अलर्ट जारी

महासमुंद। आमाकोनी रेंज के छिंदौला के पास डेरा जमाए 19 हाथियों का दल ओड़िशा से करीब पहुंच गया है। बुधवार रात हाथियों का दल छिंदौला से डूमरडीह, धौराभाठा, डूमरडीह को पार करते हुए बोडराभाठा के जंगल के समीप पहुंच गया। गुरुवार सुबह रेडियोकॉलर हाथिनी चंदा की लोकेशन के अनुसार हाथी बोडराभांठा के पास नजर आए। बाद वन अमला ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। वन अमला ने बताया कि हाथी पिछले सप्ताह भर से आमाकोनी सर्किल में विचरण कर रहे हैं। बता दें कि हाथियों का दल बीते सप्ताह भर से बागबाहरा क्षेत्र में डेरा जमाए हैं। पलारी क्षेत्र के रोहांसी से पहुंचे 17 हाथियों के दल ने कुकराडीह बंजर को नया ठिकाना बना लिया है। बीते चार-पांच दिनों से दल परसाडीह और कुकराडीह के पास डेरा जमाए हैं। हाथियों ने परसाडीह में कच्ची ईंट को रौंदकर नुकसान पहुंचाया। हाथियों के दहशत से ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़ाई के लिए जंगल नहीं जा पा रहे।

स्वावलंबन रेडी-टू-ईट बनाकर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में आई समृद्धि

जिले में महिलाओं एवं बच्चों के सुपोषण के लिए दिया जा रहा पौष्टिक आहार

राजनांदगांव। नौनिहालों का सुपोषण शासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना सुपोषण अभियान का संचालन राजनादगांव जिले में सफलतापूर्वक किया जा रहा है योजना के माध्यम से कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उन्हें कुपोषण मुक्त किया जा रहा है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमति तनूजा सलाम के निर्देशन में स्व सहायता समूह की महिलाएं रेडी-टू-ईट बनाकर आंगनबाड़ी में सप्लाई का कार्य निर्बाध रूप कर रही हैं।

ग्राम खुटेरी विकासखण्ड राजनांदगांव की जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाएं रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से कर रही हैं। समूह में कुल 14 महिलाएं है, सभी महिला सदस्य 2-3 एकड़ जमीन पर खेती कार्य करते हैं जिससे खेती से प्राप्त उपज गुजर बसर के लिए ही हो पाती है साथ ही मजदूरी कार्य भी करते हैं किन्तु इतनी आय से परिवार का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है समूह की महिलाएं जब से रेडी टू ईट बनाने के कार्य से जुडी हैं तब से इन्हें अतिरिक्त आय हो रही है जिस से इन्हें परिवार के भरण पोषण में

सुविधा हो रही है महिलाएं माह में करीब 15 दिन तक रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य करती हैं।

एनआरएलएम योजना के समूह को आर्थिक सहायता के रूप में 15 हजार रूपए का चक्रीय निधि की अनुदान राशि एक लाख 60 हजार रूपए की सी.आई.एफ राशि एवं 2 लाख 10 हजार रूपए न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक लोन दिलाया गया ताकि समूह के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध रहे। समूह द्वारा प्रति माह लगभग 35 म्टिंल रेडी-टू-ईट का निर्माण किया जाता है रेडी-टू-ईट के निर्माण में 42 रूपए प्रति किलो की लागत आती है, निर्माण में लगने वाले सभी सामग्री जैसे अनाज, तेल, नमक, गुड़ इत्यादि बाजार से थोक रेट में खरीदते हैं, रेडी-टू-ईट निर्माण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है सभी सदस्यों की जिम्मेदारी तय होती है जिसका सभी सदस्य पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं तैयार रेडी-टू-ईट को पैकेजिंग कर आबंटित आंगनबाड़ी में सप्लाई की जाती है सप्लाई के पश्चात् 50 रूपए प्रति किलो ग्राम की दर से महिला बाल विकास विभाग द्वारा समूह को भुगतान किया जाता है। सभी तरह के आय व्यय का नियमित हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है आय व्यय वर्ष सी.ए. ऑडिट भी कराया जाता है जो समूह के सुव्यवस्थित संचालन को प्रदर्शित करता है। ऑडिट रिपोर्ट समूह की बैठक में प्रस्तुत की जाती है एन.आर.एल.एम. योजना के आधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल में भ्रमण कर समूह की गतिविधि एवं आय व्यय का निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक सुझाव दिया जाता है।

वीरामगाम से चांपा स्पेशल श्रमिक ट्रेन से पहुंचे 521 श्रमिक

- मुख्यमंत्री बघेल के प्रति जताया आभार,
- चांपा रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में की गई स्वास्थ्य जांच, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं

जांजगीर चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के 521 श्रमिक को लेकर वीरामगाम (गुजरात) से स्पेशल ट्रेन आज रात 8.30 बजे चांपा रेलवे स्टेशन पहुंची। चांपा रेलवे स्टेशन पहुंचते ही श्रमिकों के चेहरे पर सुकून और खुशी के भाव थे। गत करीफ 40 दिनों से लाकडाउन में फंसे सभी श्रमिकों ने अपने गृह जिला जांजगीर-चांपा पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। जिला प्रशासन द्वारा चांपा रेलवे स्टेशन पर पूर्व से ही प्लेटफार्म को स्वच्छता, मजदूरों के लिए भोजन, पेयजल , और स्वास्थ्य जांच की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में रेल में सवार सभी 521 श्रमिकों को स्वल्पाहार, पेयजल उपलब्ध कराया गया। इसके बाद 2-2 बोगी के अंतराल में श्रमिकों को ट्रेन से उतारकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खंडवार स्थापित स्वास्थ्य विभाग के स्टालों में थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच की कार्यवाही की गई । श्रमिकों को उनके विकासखंड वार बसों में बैठाया गया और उनको कवारंटीन सेंटर के लिए रवाना किया गया।

कलेक्टर ने किया श्रमिकों का मार्गदर्शन- गुजरात के पलोडा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चांपा पहुंचे मजदूरों का ट्रेन से उतरने के बाद कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक और जिला पंचायत सीईओ श्री तीर्थराज अग्रवाल गांव और विकास खंड का नाम पूछते हुए श्रमिकों को प्लेट फार्म में उनके निर्धारित स्थान पर जाने मार्गदर्शन करते रहे।

मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

गुजरात के पलोडा में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करने गए जांजगीर-चांपा जिले के विकास खंड पामगढ़ के ग्राम मुलमुला की जानकी बाई,निक्की,सिल्ली के चंदराम, अनिल टंडन,,चंडीपारा पामगढ़ के छेरका खरे,मनबाई और गंगाधर रेल की लंबी यात्रा के बाद भी अपने गृह जिला पहुंचने पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आप लोगों को गुजरात से चांपा रेल से किसने लाने में मदद की, पूछने पर उन्होंने झट से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नाम लिया। इन सभी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया।

कलेक्टर ने किया स्टालो का निरीक्षण - कलेक्टर श्री पाठक और जिला पंचायत सीईओ श्री तीर्थराज अग्रवाल ने ट्रेन आने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बनाए गए स्टॉलो का निरीक्षण किया।

बाजोरिया फाउण्डेशन ने किया भोजन वितरण - चांपा स्टेशन में बाजोरिया फाउण्डेसन के द्वारा श्रमिक यात्रियों को भोजन वितरण किया गया। बाजोरिया फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री राजेश बाजोरिया ने बताया कि लाक डाउन के तीनो चरणों में चांपा नगर पालिका क्षेत्र में निःशुल्क भोजन व सूखा राशन विरतण किया गया।

कलेक्टर ने किया स्टालों का निरीक्षण- इसके पूर्व कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक और जिला पंचायत सीईओ श्री तीर्थराज अग्रवाल ने विकास खंड वार बनाए गए प्रत्येक स्टाल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।इसके पूर्व श्रमिकों के चांपा रेलवे स्टेशन आगमन पर कलेक्टर, एस पी, जिला पंचायत सीईओ और अधिकारियों, कर्मचारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर, चांपा एसडीएम श्री बजरग दुबे, स्टेशन मास्टर श्री दीपक सरकार, सीएमएचओ डॉ एस आर बंजारे, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

न्यूज गैलरी

बचेली पुलिस को मिली सफलता, 4 जुआरी पकड़ाए

बचेली। 13 मार्च की रात में थाना प्रभारी मनीष नागर को मुखबीर से सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 5 आनंद के घर के पास कुछ लोगो द्वारा सार्वजनिक स्थान में जुआ खेला जा रहा हैं तत्काल ही थाना प्रभारी ने टीम को रवाना किया जिसके बाद टीम ने पाया की कुछ लोग स्ट्रीट लाइट के उजाले में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे है। टीम ने घेराबंदी कर 4 जुआरियों को मौके पर पकड़ा जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम आनंद,सोमन ,बुधराम,जयलाल जुआ खेलते पकड़े गये फड़ से कुल 9250 रुपए,ताश की 52 पत्तो की गड्डी,एक चटाई जप्त की गई जिसके बाद जुआरियो को थाने लाकर उनके ऊपर धारा 13 (क)सार्वजनिक जुआ अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मनीष नागर,प्रधान आरक्षक प्रह्लाद निर्मल,आरक्षक विक्रांत साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सांसद ने किया नहर लाइनिंग कार्य का निरीक्षण

बीजापुर। बस्तर सांसद दीपक बैज शुक्रवार को बीजापुर प्रवास पर थे। सांसद ने इस दौरान ग्राम पंचायत कोडोली में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल संसाधन विभाग के नहर लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया। बैज ने कार्य में लगे मजदूरों से मजदूरी दर एवं भुगतान संबंधी जानकारी ली। मजदूरों ने बताया कि वे इस कार्य मे विगत एक माह से कार्य कर रहे हैं। उन्हें 190 रु प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हो रहा है। सांसद ने नहर लाइनिग कार्य को क्षेत्र के लिए वरदान बताते हुए प्राथमिकता के रूप में कार्य करने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले में संभावित सिचाई परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक विक्रम शाह मण्डावी ने सांसद को अवगत कराते हुए बताया कि जिले में 24 सिंचाई तालाब है, जिनका जीर्णोद्धार कर क्षेत्र के सिंचाई सुविधाओ को बढ़ाया जा सकता है। सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए भविष्य में इसे केंद्र शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग ईई जे पी सुमन, एपीओ मनरेगा मनीष सोनवानी एसडीओ जनपद पंचायत भैरमगढ़ एम आर नेताम के अलावा मैदानी स्तर के तकनीकी अमले व कर्मचारी उपस्थित थे।

पढ़ाई तुंहार दुआर के लिए मीडिया सेल का गठन

मुंगेली। जिले में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुंहार दुआर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने एवं इस योजना के प्रचार -प्रसार हेतु एससीईआरटी रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया सेल का गठन किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी जी पी भारद्वाज ने जिला मीडिया सेल का गठन सम्बन्धी आदेश जारी भी कर दिया। जिला नोडल अधिकारी पी सी दिव्य ने जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया सेल के गठन से इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जावेगा। जिला मीडया सेल के प्रभारी आकाश सिंह परिहार एपीसी समग्र शिक्षा होंगे वही शाकीय पूर्व माध्यमिक शाला धरदेई के शिक्षक अमित सोनी,प्राथमिक शाला गोरखपुर के सहायक शिक्षक विक्रम देवांगन तथा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला मुंगेली के सहायक ग्रेड 3 वीरेश पाठक इसके सदस्य बनाये गए है।

विधायक ने राशन किट वितरण वाहन को हरी झंडी दिखा किया रवाना

- अध्यक्ष निधि से विभिन्न वार्डो को चिन्हांकित कर प्रभावित परिवारों को किया जा रहा राशन किट का वितरण।

बचेली। लॉक डाउन प्रभावित परिवारों को अध्यक्ष निधि से राशन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुआत आज वार्ड क्रमांक 9 से की गई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक माननीय देवती महेंद्र कर्मा जी के द्वारा राशन किट वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही विधायक माननीय देवती महेंद्र कर्मा,कांग्रेस प्रदेश सचिव श्री छबीन्द्र कर्मा,जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह गौतम द्वारा प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। कुछ लोगो को सामग्री के वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वार्ड के लोगो की समस्याओं को विधायक महोदया ने सुना एवं मौके पर ही सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आदेश दिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह गौतम ने बताया की जिले में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे इसके लिए निरंतर हमारे द्वारा प्रयास किये जा रहे है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए की जिले के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के लाभ को पहुंचाना। आपको बता दे की नगरपालिका क्षेत्र में लॉक डाउन की शुरुआत से पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा साव एवं उपाध्यक्ष उस्मान खान सक्रिय रूप से टीम बनाकर लाकडाउन में प्रभावित परिवारों को राशन मुहैय्या करवा रहे है। अध्यक्ष निधि से जितने भी प्रभावित वार्ड है उन वार्डो को चिन्हांकित करके प्रभावित परिवारों को ये किट वितरित की जाएगी। वर्तमान में नगरपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के कार्यो की नगर में खूब सराहना हो रही है। आज के इस राशन किट वितरण कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा साव,उपाध्यक्ष श्री उस्मान खान, कांग्रेस प्रदेश सचिव श्री छबीन्द्र कर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अवधेश गौतम, संजीव साव,वार्ड पार्षद अप्पू कुंजाम ,दमयंती साहू,रीना दुर्गा,लाल बघेल, एल्डरमैन रघु,सोनवानी जी,गोपाल ,शुशीला, वरिष्ठ कांग्रेसी हीरालाल,नरेंद्र सोनी,उमेश सिंह गौतम,जीएस कुमार,रसपाल सिंह सग्गू,प्रताप मन्ना, राजेन्द्र छोटू, बबलू सिंह, बंटी, मोनु आदि कांग्रेसियों की मौजूदगी रही।

थाना सरगांव की कार्यवाही, अंतरजिला चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंगेली। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में देश प्रदेश में लागू लाक डाउन को अनदेखा करते हुए थाना सरगांव क्षेत्र में माह अप्रैल में लगातार चोर गिरोह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नकबजनी का अपराध किया जा रहा था।

इसी तारतम्य में विगत दिनो बीती रात के रात्रि चुनचुनिया निवासी मंगलू निशाद के घर का पीछे का दरवाजा खोल कर अज्ञात चोर नकदी रकम, चांदी जेवर तथा मोबाइल कुल कीमत ?13000 का चोरी कर लिया गया था रिपोर्ट पर थाना सरगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी कि इसघटना के 12 दिन बाद थाना क्षेत्र के ग्राम बावली में पिछले माह भी अज्ञात चोर गिरोह बाड़ी के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर चांदी का जेवर मोबाइल एवं नगदी रकम कीमत ?22000 का चोरी कर लिए थे थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार चोरी की घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर प्रसाद एवं सरगांव पुलिस को मामले को सुलझाने हर संभव प्रयास करने विशेष निर्देश जारी किए। इसी तारतम्य में लगातार उक्त मामलों का पर्यवेक्षण करते हुए सरगांव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के साथ-साथ सरहदी थाना जिला बलौदा बाजार, मुंगेली में माल मुलजिम की पतासाजी हेतु निर्देश देकर एवं लगातार मामले की पतासाजी किया गया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिंगारपुर थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदा बाजार के रेवाराम साहू संदीप उर्फनानू महिलांगे तथा रिपुसूदन उर्फसोनू उर्फचिटहा साहू को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ कर उक्त दोनों प्रकरण में चोरी किए गए मोबाइल, चांदी के जेवरात तथा नकदी रकम ?5000 कुल ?32400 बरामद करने में सफ्लता हासिल की। प्रकरण में पकड़े गए गिरफ्तार नकबजनीयों द्वारा शराबध् जुआ जैसे व्यसन की पूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर चोरी नकबजनी करना बताया गया पकड़े गए उक्त तीनों आरोपियों को आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

बस्तर सांसद का बीजापुर दौरा कार्यक्रम पूर्णता लाकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघनः चंद्रैया सकनी

बीजापुर। बस्तर सांसद जी का बीजापुर दौरा कार्यक्रम में पूर्णता लाकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। एक ओर कोरना वैश्विक महामारी के चलते देश- प्रदेश मे लाकडाउन चल रहा है वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद एवं विधायक नियम तोड़ते हुए भीड़ के साथ गांव में पहुंच कर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। एक ओर राज्य सरकार फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह ग्राम नहीं पहुंचा पा रही है वहीं दूसरी ओर सरकार के जिम्मेदार विधायक, सांसद भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त होना राज्य के मजदूरों के प्रति असंवेदनशील होने का प्रमाण मिलता है। इस पूरे कार्यक्रम में

क्षेत्र के जनता को कोरोना महामारी से बचाव के सावधानी का ज्ञान देने वाले जिम्मेदार सांसद एवं विधायक मास्क से मुंह और नाख ढकने के बजाय केवल जबड़े को ही ढके रखे थे। केंद्र सरकार द्वारा सत्रह मई तक लाकडाउन की घोषणा की गई है। पर लोकसभा के सांसद सभी नियमों को ताख मे रख कर अन्य जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ न सोशल डिस्टेंसिंग पालन, न धारा 144 का पालन न मास्क का ठीक से उपयोग के क्षेत्र मे पहुंच कर भीड़ वाली कार्यक्रम करना इनकी कोरोना महामारी जैसे जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

गौठान बना अतिरिक्त आय का जरिया

मुंगेली। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा,गरूवा,घुरूवा,बारी के तहत जिले मे निर्मित गौठान आय का जरिया बन गया है। निर्मित गौठानो मे स्व-सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट और नाफेड टंकी जैसी अनेक माध्यमो से जैविक खाद का निर्माण कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है। इनमे मुंगेली जिले की ऐसी स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी है। जो गौठान मे वर्मी कम्पोस्ट और नाफेड टंकी के माध्यम से जैविक खाद का निर्माण कर विगत एक वर्ष मे 2 लाख 50 हजार रूपये का अतिरिक्त आय हासिल किया है ।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्व-सहायता समूह की महिलाओ को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए निर्मित गौठानो मे रोजगार दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूह की महिलाओ द्वारा घर की कामकाज निपटाकर निर्मित गौठानो मे वर्मी कम्पोस्ट और नाफेड टंकी के माध्यम से जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। इन महिलाओ द्वारा विगत एक वर्ष में 690 क्विंटल जैविक खाद का निर्माण किया गया और उन्होने 450 क्विंटल जैविक खाद की बिक्री कर 2 लाख 50 हजार रूपये का अतिरिक्त आय प्राप्त किया। इन स्व-सहायता समूह की महिलाओ द्वारा जैविक खाद की बिक्री उद्यान विभाग और वन विभाग को किया गया है। इन विभागो द्वारा जैविक खाद का उपयोग वहां स्थापित नर्सरियो मे किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि जैविक खाद का उपयोग आज की परिवेश मे स्वास्थ्य वर्धक साबित हो रहा है।

जांच दल द्वारा कुल 12 हजार रूपए जुर्माना राशि वसूल की गई

- निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर सामग्री बेचने और प्रतिबंधित पान मसाला एवं तम्बाखू विक्रेताओं पर गिरी गाज

धमतरी। कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देश पर जिले में कोविद-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगरनिगम के संयुक्त जांच दल द्वारा आज बाजार में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, दाल, आलू, प्याज, गेहूं, नमक, तेल, आटा इत्यादि की उपलब्धता एवं कीमतों के संबंध में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में नमक की कमी होने के संबंध में अफ्वाह होने की वजह से उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में नमक क्रय कर संग्रहित किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा कृत्रिम अभाव बताकर उपभोक्ताओं से नमक का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की शिकायत मिली थी। इसके मद्देनजर संयुक्त दल ने धर्मेन्द्र किराना स्टोर्स मकेश्वर वार्ड धमतरी द्वारा अधिक दर पर नमक एवं अन्य सामग्री विक्रय करते पाए जाने पर दो हजार रूपए दण्ड शुल्क वसूली की तथा भविष्य में अधिक दर नहीं लेने संबंधी चेतावनी दी।

इसी तरह गुड्डा गैरेज धमतरी में प्रतिबंधित पान मसाला एवं तम्बाखू पाए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सेम्पल लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अमित पान सेंटर औद्योगिक वार्ड धमतरी द्वारा पान मसाला एवं तम्बाखू विक्रय किए जाने पर दस हजार रूपए जुर्माना राशि वसूली की गई। इस तरह दल द्वारा आज कुल 12 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिले में नियमित रूप से नमक की मांग के अनुसार पूर्ति की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों को नमक के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने एवं निर्धारित मूल्य पर विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। साफतौर पर कहा गया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान/व्यापारियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल प्लेटफार्म से आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का घर में हो रहा मानसिक एवं बौद्धिक विकास

अम्बिकापुर । चकमक और सजग अभियान के डिजिटल प्लेटफार्म से जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आडियो-विडियो क्लिपिंग से बच्चों को घर में ही मनोरंजन के साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास कर रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव एवं दृष्टिगत आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों का आना-जाना बंद किया गया है। इस अवधि में बच्चों के सतत् विकास के लिए अभिभावकों तक प्रारंभिक बल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा संबंधी हर संभव जानकारी पहुंचाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से चकमक एवं सजग कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

चकमक अभियान बच्चों के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मंच है जिससे बच्चों को रचनात्मक तरीके से खुद को व्यक्त करने का अवसर मिला है। बच्चों को घर में परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन करने और परिवार के साथ खुशी साझा करने का अवसर मिलता है।

ट्रेक्टर ट्राली योजना के तहत श्री बलदेव को मिला ट्रेक्टर

बीजापुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बीजापुर द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति ट्रेक्टर ट्राली योजना अंतर्गत आज जिला कार्यालय के प्रांगण में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विक्रम शाह मण्डावी, कलेक्टर के.डी. कुंजाम, पुलिस अधीक्षक कश्यप ने बलदेव चिड़ियम पिता सोमा चिड़ियम जाति परधान ग्राम पोस्ट कुटरू तहसील भैरमगढ़ बीजापुर को ट्रेक्टर ट्रॉली एवं उपकरण प्रदान किया। ट्रेक्टर ट्राली योजना में इनको स्वीकृत ऋष्ण राशि 08.74 लाख के साथ ब्याज 08 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं मर्जिन राशि 43 हजार 700 रूपये के साथ 05 वर्ष के लिए किश्त निर्धारित की गई है। विधायक मण्डावी ने बलदेव को ट्रेक्टर ट्राली से अच्छे से कार्य कर आमदनी दुगुना करने को कहा। बलदेव चिड़ियम ने ट्रेक्टर ट्राली एवं उपकरण मिलने पर विधायक विक्रम शाह मण्डावी एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

बाहर से आये मजदूरों के लिए की गई रूकने की व्यवस्था

सक्ती। इन दिनों सक्ती ब्लाक से बाहर से आये हुये मजदूरों को रूकने की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर ब्लाक से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई । जेठा कॉलेज में 200 मजदूरों की क्षमता में 159, जेठा हाईस्कूल 40 मजदूरों की क्षमता है जिसमें 58 मजदूरों को रोका गया है । टेमर हाईस्कूल में 50 मजदूरों की क्षमता है जिसमें 34 मजदूर तथा नगरदा हाईस्कूल में 100 मजदूरों की क्षमता है वहां 55 मजदूरों को रखा गया है । कुल मिलाकर 306 मजदूर इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में अभी क्वारेंटाईन में रखा गया है । मजदूर बाहर नही निकले कहके गेट में ताला तथा सुरक्षा एवं भोजन की व्यवस्था अंदर में की गई है । जब से मजदूर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आये है उनके लिये रूकने की व्यवस्था की गई है तब से नागरिकों ने घर से निकलना कम कर दिया है, कोरोना के डर से, अगर नागरिक बाहर निकलना चाहते है तो अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर अपना समय बिताते है । भोजन की व्यवस्था हर सेंटरों में की गई है ।

स्वास्थ्य विभाग के अमले को निरंतर मुस्तैद होकर कार्य करने के दिये निर्देश

■ **दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगो से जिले को सुरक्षित रखने क्वारंटाईन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक**

सूरजपुर। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अष्वनी देवांगन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.एस.सिंह की उपस्थिति में दूसरे प्रांत से आने वाले लोगों से जिले को सुरक्षित रखने क्वारंटाईन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने बताया कि वर्तमान में सूरजपुर जिला ग्रीन जोन में है और कई दिनों से कोरोना संबंधी पॉजीटिव मरीज भी सामने नहीं आये हैं, इस हेतु यह आवष्यक है कि जिले की अंदरूनी सुरक्षा इसी प्रकार बरकरार रहें। इसके लिए प्राथमिक तौर पर बाहरी प्रांतों से आने वाले लोगों का संपर्क जिलेवासियों से क्वारंटाईन की अवधि व समूचित स्वास्थ्य जांच के न हो इसे सुनिष्चित करना आवष्यक है। उन्होनें सभी विकासखंड के चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए किये

जा रहे कार्यो की जानकारी ली। जिसपर उन्होनें जिले में बनाये गये क्वारंटाईन सेंटर में बाहर से आये हुए लोगो के स्वास्थ्य परीक्षण पर समीक्षा करते हुए क्वारंटाईन में लोगों को 28 दिन तक रखने के लिए अधिकारियों को निर्देष दिये तथा किसी को भी क्वारंटाईन अवधि पूर्ण किये बिना नहीं छोडने कहा। संदिग्धों का सेंपल लेकर उचित स्वास्थ्य जांच कराने के साथ जो सेंपल जांच के बाद निगेटिव आते हैं उन्हें होम क्वारंटाईन करते हुए सख्ती से सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के निर्देष दिये हैं। उन्होनें जमात में शामिल हुए लोगों सहित बाहरी होटलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की उचित काउंसलिंग के माध्यम से पहचान करते हुए उनका सेंपल लेकर जांच कराने एवं उन्हें क्वारंटाईन करने के निर्देष दिये। जिससे किसी भी प्रकार से जिले के अंदर लोगों की सुरक्षा को खतरा न हो। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य अमलों को प्राथमिक संपर्क में किये गये जांच रिपोर्ट में पॉजिटिवों की जानकारी, निगेटिव सेंपलो की जानकारी, एंबुलेंस की जानकारी, डाईवर की व्यवस्थाओं के संबंध में उचित चार्ट बनाने कहा जिससे सही जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। पूर्व से ही पर्याप्त रेपिड टेस्ट किट, मास्क आदि उपलब्ध रहे जिसकी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देष दिये।

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में चलाया गया सेनिटाइजेशन अभियान

अम्बिकापुर। जेल अधीक्षक श्री राजेन्द्र गायकवाड़ के मार्गदर्शन में स्थानीय नगर निगम अम्बिकापुर के सहयोग से 14 मई एवं 15 मई 2020 को नगर निगम अम्बिकापुर के टीम द्वारा प्रभारी श्री अंजनी तिवारी के नेतृत्व में केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के समस्त बंदी बैरकों, जेल अस्पताल एवं महिला प्रकोष्ठ को जेल अधिकारी एवं कर्मचारियों की सुरक्षित अभिरक्षा में सेनिटाइजेषन किया गया। जेल अधीक्षक श्री राजेन्द्र गायकवाड़ ने बताया है कि जेल प्रषासन कोविड-19 के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु जेल में शासन के निर्देषानुसार समस्त आवष्यक प्रबंधन किया गया है। जेल में पृथक आइसोलेषन वार्ड भी बनाया गया है जहाँ नये आमद के बंदियों को रखा जा रहा है। सेनिटाइजेशन में नगर निगम अम्बिकापुर के टीम में प्रभारी अंजनी तिवारी, फायर मैन-श्री महेष चौबे, श्री विकास पाण्डेय, श्री सुनिल लकड़ा, श्री रविन्द्र यादव, श्री गुलषन तिवारी एवं वाहन चालक श्री संतु राम का सहयोग रहा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में पहुंचे 42 करोड़ 61लाख 73 हजार रूपये

कॉंकेर। छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष / राज्यमंत्री भरत मटियारा ने सरोना मे पंजीकृत किसानों के फसल बीमा योजना को लेकर बैठक लिया गया।जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की देते बताया की कांकेर जिले मे 35 लेम्पस है। जिसके तहत कुल 26395 पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 426173000/- रूपये राशि किसानों के खातें मे दी गई इसी प्रकार पुरे छत्तीसगढ़ मे 1333 लेम्पस है जिसमे किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया होगा और उन्हे भी इस योजना के तहत लाभ मिला होगा। जहाँ एक ओर वर्तमान समय मे कोरोना वायरस (कोविड 19) के कारण किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे है वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि वितरण से किसानों को राहत अवश्य मिली होगी।बैठक मे प्रमुख रूप से भरत मटियारा के साथ जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तारा ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवंत सुरोजिया, जनपद सदस्य चिन्तामणि रामटेके, सरपंच सरोना सुरज कुंजाम, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच जीवन नेताम, पूर्व जनभागीदारी सदस्य भरत निषाद, डॉ. बी. एल. साहु एवं अन्य उपस्थित थे।

नपा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सफाई व पेयजल का जायजा लेने भ्रमण कर रहे वार्डो का

कोंडागॉव। नगरपालिका के वार्डो की सफ़ाई वयवस्था व पेयजल व्यवस्था देखने वार्डो का भ्रमण कर रहे हैं।

जानकारी देते नपा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मियो के चलते पेयजल व निस्तारी की समस्या न हो इसके लिए पहले ही प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि नागरीय क्षेत्र के वार्ड वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े वहीं। वे लगातार वार्डो में भ्रमण वार्ड वासियों के राशन कार्ड व अन्य मूलभूत सुविधाओं से रूबरू हो रहे है।जिससे वे

शासन की योजनाओ को उनतक पहुंचा सके। नपा उपाध्यक्ष में बताया की अभी बड़ी समस्याएं उन प्रधानमंत्री आवास के हितग्रहियों की है जिनका घर निर्माणाधीन है,आने वाले दिनों में प्राथमिकता के साथ उन निर्माणाधीन मकानों को भी जल्द ही पूर्ण करवाना है,जिससे बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से वे हितग्राहियो को बचाया जा सकें।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मास्क एवं सेनिटाइजर किया गया वितरित

सूरजपुर। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में अपर कलेक्टर श्री एस0एन0 मोटवानी के द्वारा जिले में सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को सेनिटाईजर एवं मास्क का वितरण कराया जा रहा है इसी कड़ी में आज जिला कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिलाध्यक्ष श्री आदेष कुमार रवि की उपस्थिति में सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मास्क एवं सेनिटाईजर का वितरण किया गया साथ ही वहॉ

उपस्थित अन्य कर्मचारियों व आमजनों को भी मास्क व सेनिटाईजर दिया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छ रहने एवं नाक, मुहं को मास्क से ढकने व सेनिटाईजर से हाथ को बार-बार सेनिटाईज करते रहने कहा है।

उल्लेखनीय है कि जिलाप्रषासन की पहल से प्रत्येक विकासखण्डो में चतुर्थ श्रेणी के संघ अध्यक्षों के माध्यम से मास्क एवं सेनिटाईजर वितरण किया जा रहा है। जिले में 600 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है।

मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं वक्फबोर्ड के पदाधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 हजार रुपये का दान

सूरजपुर। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भुपेष बघेल जी के आव्हान पर विभिन्न स्तरों के लोगो व संस्थाओं के द्वारा बड़ी संख्या में आगे आकर राहत कोष में दान किया जा रहा है। जिससे शासन दिहाड़ी श्रमिक, गरीब बेसहारा, दिव्यांगो सहित बाहर से आकर प्रदेष में लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं को राहत पहॅुचा रहा है। इसी क्रम में आज मेंहदी हसन मुस्लिम अल्पसंख्यक पदाधिकारी, मो0 इस्राइलवक्फ बोर्ड के संभागिय अध्यक्ष एवं उपेन्द्र राजवाड़े व मो0 हासीम के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अष्वनी देवांगन के द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

आयुर्वेद विभाग ने प्रतापपुर ग्राम बोझा में वितरित किया त्रिकटू चुर्ण

■ **नगरपालिका अध्यक्ष सूरजपुर समेत प्रतिनिधियों को अपर कलेक्टर की उपस्थिति में वितरण किया गया चुर्ण व च्यवनप्रास**

सूरजपुर। आज 15 मई 2020 को आयुष विभाग द्वारा प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बोझा के हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर एवं ग्राम पंचायत भवन में शासन की मंषानुसार कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में आयुष विभाग के प्रतापपुर सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह एवं आयुर्वेद औषधालय प्रभारी डॉ प्रणिता चंद्रिका पुरे द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के

अनुसार त्रिकटु चूर्ण का वितरण किया गया और स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें गोल्डन मिल्क बनाने एवं तुलसी काली मिर्च गिलोय मुनक्का पीपली और गुड़ स्वादानुसार डालकर रोगप्रतिरोधकहरबल चाय बनाने, प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम करने के बारे में बताया गया और अपने आस-पड़ोस नाते रिश्तेदारों को भी जागरूक करने की अपील की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बोझा के सरपंच श्री कमलेश सिंह टेकाम, पंच मीठ्ठल सिंह सीताराम विष्णु दत्त मिश्रा हीरा मिश्रा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पदस्थ एनम गीता राय प्रेमलता आयुर्वेद फार्मासिस्ट राकेश पांडे बिंदेश्वर एवं समस्त उपस्थित टीकाकरण में उपस्थित लाभार्थी व समस्त ग्रामवासी बोझा कुल 95 लोगों को त्रिकटु चूर्ण एवं जागरूकता हेतु पामप्लेट का वितरण किया गया

आज 15 मई 2020 को सूरजपुर में नगर पालिका अध्यक्ष के निवास में एडीएम श्री एस.एन.मोटवानी की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष श्री केके अग्रवाल एवं पार्षद गण व अन्य जनप्रतिनिधियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने त्रिकटु चूर्ण, चवनप्राश एवं पामप्लेट का वितरण किया गया तथा हर्बल टी एवं गोल्डन मिल्क बनाने की विधि बताई गई तथा शासन द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु जारी की गई गाइडलाइन से भी अवगत कराया गया।

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR (S&P:Gen)
No. 03-03/Tn-S-785/20/252 Raipur Dtd 14/05/2020
E-TENDER NOTICE NO. TN-s-785/TS-1080/20
Online bids are invited by the undersigned through CSPCL e-bidding system from Experienced & reputed contractors for the work as mentioned below for KTPS, Korba (East):-

RFx No. (E-Tender No.)	Particulars	Last date & time of bid submission
8100017472	Contracts for round "o" clock operation and routine general checking of various conveyors in CHP KTPS, Korba East	06.06.2020 up to 15:00 Hrs

For more details, please visit our website at:- http://www.cspc.co.in/cspgcl/ Any amendment/ corrigendum, if required, will be displayed on our website only.
SAVE ELECTRICITY S-25379/1 Executive Director (S&P:Gen.) CSPGCL, Raipur (C.G.)

प्रथम पृष्ठ का शेष...

कंटनमेंट जोन को छोड़...

के लिए अनुमति दी जा सकती है। होटल व्यवसाय को फिजिकल डिस्टेंस के पालन की शर्तो के तहत केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति दी जा सकती है। होटलों में संचालित रेस्टोरेंट, बार, स्पा इत्यादि को अभी अनुमति न दी जाए। इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से सेवाएं देने वाले सभी प्रकार के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री इत्यादि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए साथ ही उनको अपने टूल्स, उपकरण एवं अन्य सामग्री के लिए दुकान संचालन की भी अनुमति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि राज्यों को सशक्त करने से निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में उनकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। केन्द्र शासन एवं अन्य राज्य सरकारों के सहयोग के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार है।

-फंसे लोगों के परिवहन के लिए ही हो वायुमार्ग का इस्तेमाल : इसी प्रकार वायु मार्ग से व्यक्तियों का परिवहन केवल फंसे हुए व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। सामान्य एवं गैर आवश्यक कारणों से आने-जाने की अनुमति अभी दिया जाना उपयुक्त नही होगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखा जाना उपयुक्त होगा। बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने अपना योगदान बखूबी दिया है।

अंतरराज्यीय सीमाओं को....

पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना फिलहाल आवश्यक है। केवल अत्यावश्यक कारणों से अनुमति सहित परिवहन होना चाहिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने केवल संबंधित राज्यों की सहमति से ही चलायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य कोरोना संक्रमण प्रभावित प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में पुनः संक्रमण के फैलने की आशंका है। अतः आगामी कुछ माह में सावधानी की दृष्टि से अंतर्राज्यीय सीमाएं खोलना उपयुक्त नहीं होगा।

लॉकडाउन में राज्य महिला...

होते हैं। लॉकडाउन में परिवहन व्यवस्था बंद होने की वजह से हो सकता है कम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

40 दिन तक शराब न बिकना

राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य ममता साहू का कहना है राज्य में घरेलू हिंसा के मामलों में कमी का कारण करीब 40 दिन तक राज्य में शराब नहीं मिल पाना है। जब तक शराब दुकानें बंद थी, तब तक लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। जबकि अब पहले जैसा ही हाल होने लगा है। धरमपुरा में एक महिला के पति ने शराब दुकान खुलने के बाद पीने के लिए घर बर्तन बेच दिए। इसलिए मेरा मानना है कि शिकायतों में कमी आने के पीछे डाक से भी ज्यादा बड़ा कारण शराब दुकानें बंद होना है।

किसानों की आय बढ़ाने...

का आधुनिकीकरण करने, उनमें नई टेक्नॉलजी लाने, ब्रैंड बनाने और मार्केटिंग करने में उनकी मदद के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना लाई गई। इस योजना से 2 लाख छोटी एमईएफएस को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना, जम्मू-कश्मीर में केसर, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्च आदि का जिक्र कर कहा कि इन इलाकों में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा और इनकी ब्रैंडिंग की जाएगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपयेः समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन में सम्मीलित विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। 9 हजार करोड़ रुपये आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होगा जिसमें फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, मंडियां आदि विकसित होंगे। इससे अगले पांच वर्षो में मछली उत्पादन 70 लाख टन बढ़ जाएगा, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात होगा।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमः पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 53 करोड़ पशुओं को मुंहपका, खुरपका रोगों से निजात मिलेगी। इससे हमारे पशु उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी। इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैसों का टीकाकरण हो चुका है।

औषधीय पौधों की खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपये : नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती में मदद की है। अगले दो सालों में 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इस फंड से औषधीय पौधों की क्षेत्रीय मंडियां विकसित की जाएंगी। गंगा नदी के किनारे-किनारे 800 हेक्टेयर एरिया में मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर विकसित करेगा।

मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की योजनाः इससे 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। बीकीपिंग डिवेलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यु अडिशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

कोरोना से मरने वाले...

संख्या 2649 हो गई है। जबकि 82 हजार से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका है जहां संक्रमितों की संख्या 14 लाख 57 हजार 649 हो गई है। जबकि यहां 86 हजार 912 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों के मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है। यहां 2 लाख 74 हजार 367 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि मौतों के मामले में अमेरिका के बाद इटली है, जहां 31 हजार 368 लोगों की मौत हो चुकी है।

पूरा वेतन नहीं...

अदालत से कहा कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान संगठनों को उनके कार्यबल (वर्कफोर्स) को पेमेंट करने से पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए। याचिका मुंबई के एक कपड़ा फर्म और 41 छोटे पैमाने के संगठनों के एक पंजाब आधारित समूह की ओर से दायर की गई थी।

याचिका में गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को रद्द करने मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ढ्ढ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। पंजाब स्थित लुधियाना हैंड टूल्स असोसिएशन ने दावा किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 29 मार्च को दिया गृह मंत्रालय का आदेश, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(त), 265 और 300 का उल्लंघन है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-1 दिनांक 08.05.2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

टेन्डर सिस्टम नम्बर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
63946	जिला-सूरजपुर विकासखण्ड प्रेमनगर ग्राम-केदारपुर अंतर्गत जल वितरण वाहिनी हेतु 90 मि.मी. व्यास के 6 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेमी यू.पी.व्ही. सी. पाईप 3643 मीटर, 110 मि.मी. व्यास के 6 कि.ग्रा. परति वर्ग सेमी यू.पी.व्ही.सी. पाईप 1076 मीटर, 140 मि.मी. व्यास के 6 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेमी यू.पी.व्ही.सी. पाईप 857 मीटर एवं 90 मि.मी. व्यास के 10 कि.ग्रा. प्रतिवर्ग सेमी यू.पी.व्ही.सी. पाईप 880 मीटर, कुल 6456 मीटर यू.पी.व्ही.सी. पाईप मय वाल्व, स्पेशल्स एवं फिटिंग इत्यादि के निरीक्षण सहित प्रदाय, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण कर चालू करना एवं 3 माह तक चलाने का कार्य आदि सम्पूर्ण कार्य।	रु. 31.55

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा दिनांक -26.05.2020 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

जी-80729/3

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सूरजपुर

कार्यालय नगर पंचायत कसडोल
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
Tel-07728-251247 E-mail id- cmoksd@gmail.com

-:: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय निविदा) ::-

क्र./403/निविदा/न.पं./लो.नि.वि./2020-21 कसडोल, दिनांक 13/05/2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से नगर पंचायत कसडोल हेतु वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित विभिन्न कार्य हेतु भण्डार क्रय नियम तथा सी.जी. पी.डब्ल्यू.डी. भवन एवं सड़क 01.01.2015 एस.ओ.आर. दर पर (समस्त संसाधनों के साथ) कम/अधिक या समान दरों फर्म "A", "B", "C" में तीन लिफाफा पद्धति में बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सभी निविदाएं स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार की जावेगी। समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

01. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय - 19/05/2020 शाम 4.00 बजे तक
02. निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि - 20/05/2020 शाम 4.00 बजे तक
03 निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय - 27/05/2020 शाम 4.00 बजे तक
04. निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय - 28/05/2020 प्रातः 11.00 बजे तक

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
01	सबमर्सिबल एवं अन्य मोटर पंप मरम्मत कार्य।	10.00
02	स्टेशनरी सामग्री एवं मुद्रण कार्य	4.00
03	फ्लेक्स बेनर छपाई कार्य	2.00
04	दीवाल लेखन कार्य	1.50
05	टेन्ट किराया	5.00
06	ट्रेक्टर, टेंकर एवं जे.सी.बी. किराया	5.00
07	लोक निर्माण सामग्री क्रय जैसे फ्लाई एस ईट/गिट्टी/मुरूम/कतरी/जीरा गिट्टी/ टाईल्स/ ग्रनाईट पत्थर/फेंनसिंग तार/सीमेंट/दरवाजा लोहे/ लकड़ी प्रदाय कार्य	10.00
08	जोनल/मरम्मत संधारण कार्य।	15.00
09	टिप्पर एवं रिक्शा मरम्मत कार्य।	5.00
10	सी.सी.टी.व्ही. कैमरा फिटिंग कार्य।	2.00

टीप :- उपरोक्त कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में लोक निर्माण शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह निविदा आमंत्रण सूचना विभाग के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर भी अवलोकन की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत कसडोल

पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथीन का उपयोग न करें।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)
(द्वितीय आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांक 02/व.ले.लि./2020-21, दिनांक 14/5/2020

बेरोजगार सिविल स्नातक इंजीनियरों को कार्यो का आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

निम्नलिखित कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर में पंजीकृत बेरोजगार सिविल स्नातक इंजीनियरों से मैन्युअल निविदा आमंत्रित किए जाते हैं कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण कार्यपालन अभियंता, हसदेव जल प्रबंध संभाग रामपुर/ कोरबा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि - 23.05.2020
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि - 29.05.2020
निविदा खोलने की तिथि - 30.05.2020

ग्रुप नम्बर	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. में)
1	2	3
01	हसदेव बांयी तट नहर के पावर केनाल के आर.डी. 3500 मी. पर स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य।	रु. 8.80 लाख
02	हसदेव बांयी तट नहर के पावर केनाल के आर.डी. 4300 मी. पर स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य।	रु. 8.80 लाख
03	हसदेव बांयी तट नहर के रिटर्न केनाल के आर.डी. 200 मी. पर स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य।	रु. 8.80 लाख

जी-80735/3

कार्यपालन अभियंता,
हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग,
रामपुर/ कोरबा

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक यशवंत धोटे द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर कुबेर प्लाजा शॉप नं. 226 सेकंड फ्लोर लिंक रोड बिलासपुर से प्रकाशित, संपादक- रविशंकर शुक्ला*
RNI NO.CHHHIN/2015/62431, डाक पंजीयन क्रमांक जी.2-112/सी.जी./बी.एल.पी./108/2020-2022, email: navpradesh@gmail.com, फोन व फैक्स : 07752-400878

महिलाओं की मदद के लिये आगे आयीं कैटरीना

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कैटरीना कैफघरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिये आगे आयी हैं।

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच कैटरीना कैफ लगातार इंस्टाग्राम पर कुछ न कुछ पोस्ट कर ही रही हैं। उन्होंने पहले गिटार बजाते हुए वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा उनके फिटनेस वीडियो भी फैंस के बीच चर्चा बटोर रहे थे। कैटरीना की लेटेस्ट पोस्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हैं। कैटरीना ने घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए काम कर रही संस्था स्नेहा की सहायता करने का फैसला किया है।देश में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही साथ घरेलू हिंसा के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते इस संस्था को फंड और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। यही कारण है कि कैटरीना ने इस संस्था की मदद के लिए ये कैंपेन शुरु किया है।इस कैंपेन के लिए स्नेहा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से एक नाम चुन कर उसे अपनी फोटो के साथ शेयर करना है। इसके बाद दी गई लिंक पर डोनेशन दिया जा सकता है। कैटरीना ने इस संस्था की मदद करते हुए अपनी फोटो पर फातिमा नाम लिखकर पोस्ट शेयर किया है। कैटरीना ने इसके अलावा जान्हवी कपूर, आलिया भट्ट और तब्बू जैसे स्टार्स को भी नॉमिनेट किया है।

कोरोना ने बदली कैटरीना की जिंदगी

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ की जिंदगी के प्रति सोच कोरोना महामारी ने बदल दी है। कोरोना महामारी ने लगभग हर चीज को बदलकर रख दिया है। इससे जिंदगी के प्रति इंसानों का नजरिया बदला है। कैटरीन का भी कुछ ऐसा ही मानना है। कैटरीना ने कहा, ÷यह महामारी और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन ने हम में से कई लोगों को आत्मनिरीक्षण करने का मौका दिया है कि हमारी जिंदगी कितनी बेहतर है या किस तरह से हम इसे आम तौर पर ले लेते हैं। इसके साथ ही मामलों की बढ़ती संख्या के कारण मेरा मानना है कि हमें अपने खानपान और जीवनशैली के माध्यम से अपनी बेहतर इम्युनिटी की दिशा में काम करना चाहिए। इसने कुछ मायनों में जिंदगी के प्रति मेरी सोच भी बदल दी है। कैटरीना ने कहा , ÷मैं यह सोचकर कभी-कभार परेशान हो जाती हूं कि जिंदगी पटरी पर कब आएगी, लेकिन दुनिया इस वक्त जिस परेशानी का सामना कर रही है मैं उसे भी समझती हूं। तनाव ऐसी स्थिति में एक गंभीर मुद्दा है।

प्राची अधिकारी ने पीएम केयर्स फंड में दिया योगदान

हल्द्वानी (वार्ता)। उत्तराखंड में हल्द्वानी के कुसमखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली प्राची अधिकारी आज दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत टॉलीवुड का माना जाना चेहरा है। प्राची ने अपनी फिल्मों के जरिये जहां लोगों का मनोरंजन कर अपने अभिनय को लोहा मनवाया है वहीं कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री केयर्स कोष में उचित धनराशि देकर अपना योगदान दिया है, लेकिन उन्होंने अपने योगदान की राशि को सार्वजनिक नहीं किया है। प्राची ने यूनीवार्ता से बातचीत में कहा कि उसने टॉलीवुड फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर अपने प्रशंसकों और लोगों का मनोरंजन किया है। वह अब तक 20 से अधिक फिल्मों में बतौर अभिनेत्री अभिनय कर चुकी हैं। उनकी दो तमिल फिल्मों को हिन्दी में भी डब किया गया है। प्राची ने महज सात साल की उम्र में अभिनय की दुनियां में पदार्पण किया। उन्होंने कहा वह अब ऐसे किरदार निभाना चाहती हैं जिसका उनके वास्तविक जीवन से किसी प्रकार का ताल्लुक न हो।

हिन्दू महासभा की ब्रांड एम्बेसेडर प्राची पीतल धातु निर्मित गणपति की प्रतिमा को हमेशा अपने साथ रखती हैं। इस प्रतिमा को वह गन्नू कहकर सम्बोधित करती हैं और अपने लिए बेहद शुभ मानती हैं। उन्होंने कहा कि ÷मैं शूटिंग छोड़ सकती हूं, मैं करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूं लेकिन गन्नू मेरे से दूर हो जाए तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अच्छे ऑफर मिलने पर ही वह हिन्दी फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी।

अक्षय ने मुंबई पुलिस को दिये 1000 रिस्ट बैंड

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस को 1000 रिस्ट बैंड दिये हैं जो कोविड 19 के लक्षणों को पहचानने में उनकी मदद करेंगे।

कोरोना वायरस से लड़ाई में अक्षय कुमार अपने स्तर पर हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उन्होंने पीएम केयर्स फंड को 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। अब उन्होंने मुंबई पुलिस को 1000 रिस्ट बैंड दिये हैं जो कोविड 19 के लक्षणों को पहचानने में उनकी मदद करेंगे। यह बैंड घड़ी की तरह कलाई पर बांध लिया जाता है। इसमें लगे सेंसर्स शरीर का तापमान, धड़कन, ब्लड प्रेशर के साथ कदमों की संख्या और कैलोरीज़ पर नज़र रखते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की पहचान के लिए सबसे ज़रूरी कदम तापमान ही है। इससे पहले मुंबई पुलिस को कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद करने के लिए अक्षय ने पुलिस फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपये का दान भी दिया था। इसके अलावा अक्षय ने बृह्नमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (बीएमसी) को पीपीई, मास्क और रैपिड टेस्टिंग किट ख़रीदने के लिए भी 3 करोड़ रुपये दान दिये थे।

विद्या बालन की 'शकुंतला देवी' ओटीटी प्लेटफार्म पर होगी रिलीज

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड में अपने संजीदा अभिनय के लिये मशहूर विद्या बालन की फिल्म 'शकुंतला देवी' ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफार्म पर रिलीज की जायेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश में लंबे वक्त से लॉकडाउन चल रहा है।कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। विद्या बालन की फिल्म 'शकुंतला देवी' ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज की जायेगी।विद्या की यह फ़िल्म आठ मई को आने रिलीज़ होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस से सिनेमाघरों के बंद होने की वजह से फ़िल्मों की रिलीज़ बंद है। विद्या ने इंस्टाग्राम पर इसकी सूचना देते हुए लिखा ,÷ यह एलान करते हुए खुश हूं कि शकुंतला देवी जल्द प्राइम वीडियो पर आप अपने परिवार के साथ देख सकेंगे।

आधुनिक हॉकी में फिटनेस का अहम रोल: नवजोत

बेंगलुरु (वार्ता)। भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड नवजोत कौर का मानना है कि फिटनेस हॉकी में अहम रोल अदा करता है और फिट रहने से खिलाड़ी मैच में उम्मीद के अनुरुप प्रदर्शन कर सकते हैं।

नवजोत ने इंस्टाग्राम लाइव सत्र में टीम के साइंटिफिक सलाहकार वायने लोम्बार्ड के साथ फिटनेस सत्र पर चर्चा की और कुछ व्यायाम भी किए। इस सत्र का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान नवजोत की फिटनेस में सुधार लाने तथा बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) कैंपस में सामाजिक दूरी का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना था।

25 वर्षीय नवजोत ने कहा, ÷मेरा मानना है कि आधुनिक हॉकी में फिटनेस अहम रोल अदा करता है। अगर खिलाड़ी फिट रहेंगे तो वे मैदान पर सही ढंग से प्रदर्शन कर सकेंगे और पूरे 60 मिनट तक उम्मीद के अनुरुप प्रदर्शन करेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी हमारे लिए अपनी फिटनेस बरकरार रखना बहुत जरुरी है और इसके लिए हमें कुछ समय व्यायाम करने चाहिए। इससे जब भी हम मैदान पर उतरें तो हमारी लय बरकरार रहेगी। सत्र के दौरान नवजोत ने पांच मिनट तक वार्मअप व्यायाम किया और लोम्बार्ड दर्शकों को हर व्यायाम को समझाते रहे। नवजोत ने चार अलग-अलग सेट के व्यायाम किए जिसमें पहले सेट में अपर बॉडी मूवमेंट शामिल था। पहले सेट में उन्होंने पुश-अप सहित कई व्यायाम किए।

लोम्बार्ड ने कहा, ÷मेरे ख्याल से यह वो क्षेत्र है जहां महिला खिलाड़ियों को ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरुरत है वो भी उस वक्त जब वे लंबे समय से ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हैं। हालांकि हमारा फिटनेस सत्र लॉकडाउन के दौरान नवजोत की फिटनेस बरकरार रखने पर केंद्रित है जिससे वह जब भी ट्रेनिंग वापस शुरु करें तो उनकी फिटनेस को लेकर कोई परेशानी नहीं खड़ी हो सके। सत्र के दौरान लोम्बार्ड और नवजोत ने कुछ प्रशंसको के सवालों के जवाब भी दिए। लोम्बार्ड से जब फिटनेस सत्र के महत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ÷खेल में फिटनेस का अहम रोल है और हॉकी में शारीरिक तौर पर फिट रहना बेहद जरुरी है। खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग और मैच के दौरान फिटनेस अभ्यास कराना जरुरी है। इससे वे मजबूत बनते हैं और उनके सहनशीलता में सुधार आता है।

आयरलैंड ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ सीरीज स्थगित कर दी

डबलिन (वार्ता)। क्रिकेट आयरलैंड ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान साथ होने वाली घरेलू सीरीज को कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया है। आयरलैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 जून से दो जुलाई तक तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी थी जबकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ 12 और 14 जुलाई को दो टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी थी। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में खेल गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं और ऐसे में आयरलैंड का इस साल सितंबर में इंग्लैंड दौरा भी संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि क्रिकेट आयरलैंड के अनुसार इस बारे में बातचीत जारी है। क्रिकेट आयरलैंड के मुख्य कार्यकारी वारेन ड्यूट्रोम ने कहा, ÷सरकार के दिशार्निदेश के अनुसार न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलना मुश्किल है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने हमें बताया है कि वह इसके लिए यहां का दौरा नहीं कर सकते हैं। हालांकि इससे हमें निराशा हुई है लेकिन हालात को देखते हुए हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा, ÷अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए यह समय काफी कठिन है और हमें आयरलैंड के अपने दोस्तों के लिए दुख हो रहा है जिनका सत्र इसके कारण बाधित हुआ है।

जून में होगी ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल

सिडनी (वार्ता)। कोरोना वायरस के खतरे के कारण मार्च में स्थगित हुई ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग (एएफएल) 11 जून से शुरु होगी। एएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिलोन मैकलाचलन ने संवाददाताओं को बताया कि सभी 18 क्लब 25 मई से ट्रेनिंग शुरु करेंगे और कार्यक्रम को चार से छह सप्ताह के अंतराल में जारी किया जाएगा।

खिलाड़ी और स्टाफका मैदान पर उतरने से पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा और सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी खिलाड़ियों, स्टाफऔर अंपायर को सप्ताह में दो बार टेस्ट कराना होगा।

मैकलाचलन ने कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने नेताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों को मैच के आयोजन की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया।

वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे सीरीज स्थगित

किंगटन (वार्ता)। क्रिकेट वेस्ट इंडीज और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस माह के अंत में जमैका और त्रिनिदाद में होने वाली महिला टीमों की एकदिवसीय सीरीज को कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया है। पांच मुकाबलों की यह सीरीज जुलाई में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर्स से पहले होनी थी लेकिन आईसीसी ने पहले ही क्वालीफायर्स को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया था जिसके बाद अब यह सीरीज स्थगित कर दी गयी है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बनी स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बोर्डों को पुरुष ए टीम का दौरा रद्द करना पड़ा है जो जून के महीने में एंटीगा में आयोजित होना था। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही महिला विश्व 2021 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

22 मई से वेस्ट इंडीज में शुरू होगी टी-10 लीग

सेंट विन्सेंट (वार्ता)। कोरोना वायरस के खतरे के कारण पूरे विश्व में बंद पड़ी खेल की गतिविधियों के बीच वेस्ट इंडीज में 22 मई से विंसी प्रीमियर टी-10 लीग शुरू होगी। वेस्ट इंडीज के सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडिंस में यह लीग खेली जायेगी। यह यह वीपीएल का पहला सत्र होगा जिसमें छह टीमें होंगी। लीग 22 मई से 31 मई तक सेंट विंसेंट के आरनोस वेल स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में खेली जायेगी।

एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे गांगुली: डेविड गॉवर

नई दिल्ली (वार्ता)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज डेविड गॉवर का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरभ गांगुली में एक अच्छे प्रशासक के सभी गुण मौजूद हैं और वह भविष्य में क्रिकेट की विश्व संस्था आईसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं।

गॉवर ने फैन्स इंटरैक्टिव शो ग्लोफ़ैन्स के साथ बातचीत में कहा कि गांगुली एक दिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में पाएंगे लेकिन उनका यह भी मानना है कि बीसीसीआई का कार्यभार संभालना किसी भी दिन एक बड़ा काम है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान गॉवर ने गांगुली की बीसीसीआई के शीर्ष बॉस के रूप में नियुक्ति के समर्थन में प्रशंसा की है। गॉवर ने स्वीकार किया कि दादा के नाम से मशहूर गांगुली एक दिन आईसीसी अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांगुली के पास सभी गुण हैं जो एक अच्छे प्रशासक के लिए जरूरी हैं। गॉवर ने कहा, ÷मैं आपको सौरभ के बारे में क्या बता सकता हूं। मैंने वर्षों से उनके साथ कई बार बातचीत की है । वह एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनके रिकॉर्ड खुद गवाह हैं। एक बात जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सीखी है, वह यह है कि अगर आप बीसीसीआई को चलाने जा रहे हैं, तो आपमें कई चीजें होनी चाहिए। उनकी जैसी प्रतिष्ठा है, वह बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आपको बहुत ही विनम्र राजनीतिज्ञ होने की आवश्यकता है। इंग्लैंड के पूर्व शीर्ष क्रम के बल्लेबाज गॉवर ने क्यू 20 में ग्लोफन्स में प्रशंसकों के लिए अनोखे चैट शो मे फैन्स से क्रिकेट के अनुभवों साझा किया। गॉवर ने कहा, ÷हम सभी जानते हैं कि भारत में क्रिकेट के लिए अपार आकर्षण है। तो यह वास्तव में एक अद्भुत बात है। सौरभ के पास बीसीसीआई के प्रभारी के रूप में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहूंगा कि अब तक संकेत बहुत अच्छे हैं÷।

क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाज गॉवर ने कहा, ÷मुझे लगता है कि वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनके पास राजनीतिक कौशल है। मुझे लगता है कि उनके पास सही रवैया है और चीजों को एक साथ रख सकते हैं और अच्छा काम करेंगे। मैं वास्तव में कहूंगा कि अधिक महत्वपूर्ण काम ईमानदार होना और बीसीसीआई चलाना है। आईसीसी का प्रमुख होना एक सम्मान है, आईसीसी के जरिये बहुत कुछ किया जा सकता है। बीसीसीआई निश्चित रूप से बड़ा काम है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के सन्दर्भ में कहा, ÷इस विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का विचार एक बहुत ही सरल कारण से आया था कि लोग टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। सत्तर, अस्सी के दशक में मुझे नहीं लगता कि हमें निष्पक्ष होने के लिए संदर्भ की आवश्यकता थी। टेस्ट क्रिकेट बहुत अधिक स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप था और अगर किसी चीज का न्याय किया जाना था, तो यह एक व्यक्तिगत और एक टीम के रूप में टेस्ट मैचों में प्रदर्शन था।

इंग्लैंड की टीम फिर से शुरू करेगी प्रशिक्षण

लंदन (वार्ता)। इंगलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तरफ कदम उठाते हुए अगले सप्ताह से पूरे देश में कई स्थानों पर नियंत्रित वातावरण में प्रशिक्षण फिर से शुरू करेगी। यह घोषणा बुधवार को सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक सलाह के बाद की गयी है जिसमें कोविड-19 के प्रकोप के दौरान खिलाड़ियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी रखने के उपायों को निर्धारित किया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस कदम का उद्देश्य इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों की चोट की संभावनाओं को कम करना है जिन्होंने श्रीलंका दौरे के बाद से क्रिकेट के मैदान पर कदम नहीं रखा है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए मैदान का चयन हालांकि अभी नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि ट्रेंट ब्रिज, एजबस्टन , ओल्ड ट्रेफर्ड, ओवल, टॉन्टन के मैदान पर प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। प्रशिक्षण की शुरुआत में खिलाड़ियों को पहले अकेले ही अभ्यास शुरू करना होगा जिसमें एक कोच और फिजियो भी शामिल होगा।

नव प्रदेश
स्थापना दिवस
बिलासपुर, शनिवार 16 मई 2020

लॉक-डाउन में आर्थिक मंदी की

चाबी बनी मनरेगा

कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉक-डाउन के कारण जहाँ एक तरफआर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हैं, वहीं बीजापुर के गाँवों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से बनी हितग्राहीमूलक परिसम्पत्तियाँ कुएँ, डबरी, निजी तालाब, पशु शेड और कम्पोस्ट पिट ग्रामीणों की आजीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण जरिया बने हुए हैं। लॉक-डाउन के इस कठिन दौर में भी उनकी कमाई अप्रभावित है और वे निर्बाध रूप से जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

बड़े राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराने में भी

छत्तीसगढ़ शीर्ष पर

105 फीसदी काम, 13.62 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन	18 जिलों में लक्ष्य से अधिक रोजगार, नक्सल प्रभावित	बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा सबसे आगे

*छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश के लिए स्वीकृत 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार के विरूद्ध यहां 13 करोड़ 61 लाख 84 हजार 269 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। यह लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। मनरेगा में लक्ष्य के विरूद्ध प्रदर्शन के मामले में **छत्तीसगढ़ देश** के सभी बड़े-छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। इस मामले में केरल, नागालैंड और मेघालय ही प्रदेश से आगे है।*

लॉकडाउन के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत शुरू किए गए व्यापक कार्यों से कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है। लॉक-डाउन के बाद अकेले अप्रैल महीने में ही नए और पुराने कार्यों को मिलाकर कुल 548 करोड़ 41 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। राज्य शासन द्वारा सामग्री मद में भुगतान के लिए भी 210 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार के लिए 76 करोड़ 94 लाख रूपए भी शीघ्र जारी किए जाएंगे।

राज्य के सभी जिलों में सबसे ज्यादा रोजगार राजनांदगांव में..

राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक एक करोड़ 46 लाख 36 हजार मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

- बिलासपुर में 84 लाख 74 हजार मानव दिवस,
- कबीरधाम में 84 लाख 30 हजार,
- सूरजपुर में में 71 लाख 53 हजार,
- बलौदाबाजार-भाटापारा में 68 लाख 25 हजार,
- बालोद में 66 लाख 87 हजार,
- कांकेर में 64 लाख 53 हजार,
- गरियाबंद में 60 लाख 96 हजार,
- धमतरी में 59 लाख 85 हजार,
- महासमुंद में 57 लाख नौ हजार,
- कोरिया में 53 लाख 69 हजार,
- जशपुर में 53 लाख 47 हजार,
- बलरामपुर-रामानुजगंज में 50 लाख 24 हजार
- जांजगीर-चांपा में 48 लाख 74 हजार

मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है।

मनरेगा के कार्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही है मजबूती

कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी के विषम परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संचालित कार्य मजदूरों के लिए सार्थक कदम हो रहा है। लॉकडाउन में मेहनतकश मजदूर कार्य के दौरान जरूरी दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 01 अप्रैल 2020 से मजदूरी दर 176 रू. से बढ़ाकर 190 रू. किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। मनरेगा एपीओ शशिकान्त गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिले में वर्तमान में अभी कुल 27177 पंजीकृत मजदूर कार्य कर रहे है एवं आठ जनपद पंचायतों में कुल 2895 कार्य संचालित है, जिसमें मजदूरों के मांग के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी

निर्माण कार्यों के दौरान मैदानी अमलों को नरेगा कार्य संचालन हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यस्थल पर मास्क, हैण्डवाश व साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, एवं कार्य के पूर्व मजदूर जागरूक होते हुए स्वयं हैण्डवाश/साबून से बार-बार हाथ धोकर व मास्क लगाकर कार्य कर रहे है। इस हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों को कार्य के दौरान इनका पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। योजनान्तर्गत कृषि संबंधी कार्य एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत जल संरक्षण व जल संवर्धन के कार्यों को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है।

नए वित्तीय वर्ष में 19 लाख 85 हजार166 मजदूरों को मिला रोजगार

नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले दिन 1 अप्रैल को प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की संख्या केवल 57 हजार 536 थी। लॉक-डाउन के मौजूदा दौर में गांवों में काम की जरूरत को देखते हुए सरकार द्वारा जोर-शोर से मनरेगा कार्य शुरू कराए गए। मैदानी अमले और सरपंचों की सक्रियता से महीने के आखिर में 30 अप्रैल को यह संख्या 19 लाख 85 हजार 166 जा पहुंची।

जॉबकार्डधारी को एक करोड़ 23 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध

इस दौरान मनरेगा जॉबकॉर्डधारी 10 लाख 24 हजार परिवारों को एक करोड़ 23 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण कर श्रमिकों को त्वरित भुगतान भी किया गया। अप्रैल माह में काम करने वालों को 200 करोड़ रूपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया गया है।

मनरेगा कार्यों में सबसे ज्यादा 18 जिलों ने पैदा किया रोजगार

हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों में प्रदेश के 18 जिलों ने लक्ष्य से अधिक दिनों का रोजगार सृजन किया है। शेष नौ जिलों में भी रोजगार सृजन 91 से 99 प्रतिशत तक है। मनरेगा में नक्सल प्रभावित जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा प्रदेश में लक्ष्य के विरूद्ध सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जिले हैं। बीजापुर 219 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के साथ प्रदेश में सबसे आगे है। सुकमा 149 प्रतिशत, नारायणपुर 128 प्रतिशत और दंतेवाड़ा 123 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर है।

मनरेगा दे रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

लॉकडाउन के बीच ग्रामीणों को मिला गांव में ही काम

जहां कोरोना संकट के मद्देनजर शासन ने 14 अप्रैल से 3 मई तक लाकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। वहीं इस संकट की घड़ी में शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना 'नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी एवं मनरेगा' जैसे रोजगारमूलक कार्य ग्रामीणों के लिये संजीवनी बूटी की तरह मददगार साबित हो रहे हैं और साथ ही लोगों के जीवन में नया उत्साह व आशा भरने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को रोजगार दिलाने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के 137 ग्राम पंचायतों में 530 कार्य प्रगति पर है जिसमें 16 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा हैद्य यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है। सुकमा जैसे संवेदनशील व बीहड़ क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायतों में आजीविका के साधन अत्यंत सीमित हो गये थे, लोगों के जहन में जहां रोजी-रोटी व परिवार के भविष्य की चिंताएं घर करने लगा था। वहां ऐसे में नरवा, गरवा, घुरवा, एवं बाड़ी तथा मनरेगा योजना के तहत् विभिन्न निर्माण कार्य प्रारंभ होने से गांव के लोगों की चिंताएं दूर हो रहीं है। मनरेगा में छोटे व गरीब तबके के लोगों को रोजी-रोटी के लिये सरल व सहज साधन मिल रहा है। मदद के रूप में ग्राम वासियों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। जिले में लॉकडाउन के दौरान शासन-प्रशासन द्वारा सभी निजी श्रमिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है वहीं सामाजिक-अंतराल रखते हुये मनरेगा कार्यों को अनुमति दिया गया है। जिले के 153 में से 137 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 530 कार्यों में 16 हजार से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान पंचायतों के सरपंच, पंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा कार्य स्थल पर मजदूरों के बीच सामाजिक अंतराल बनाये रखने, कार्य के पूर्व व बाद में तथा खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धुलाई, मास्क अथवा साफ कपड़े से मुंह ढंकने हेतु जागरूक करने के साथ-ही साथ आवश्यक सामग्री जैसे साबुन, मास्क, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। गांव में ही रोजगार मिलने व समय पर सतत् मजदूरी राशि मिलने से मजदूरों व ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। मनरेगा अंतर्गत गांव के अंदर या नजदीक में ही व्यक्तिगत व रोजगार मूलक एवं अति-आवश्यक कार्यों जिससे बरसात के पूर्व पर्याप्त मात्रा में जल संचयन किया जा सके व आजीविका सृजित हों उनको प्राथमिकता देते हुये कराया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

यूपीआई नियमों को लेकर गूगल पे पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। यूपीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गूगल पे पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस आशा मेनन ने आरबीआई, केंद्र सरकार, गूगल इंडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा और इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गूगल पे ने उन्हें नया वीपीए या यूपीआई आईडी बनाए बिना पीएम केयर्स फंड में अंशदान की इजाज नहीं दी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता शुभम कापाले ने अपने मौजूदा वीपीए/यूपीआई आईडी से दूसरे लेनदेन की भी कोशिश की, लेकिन यही बाधा आई।

रुपया दो पैसे टूटा

मुंबई (वार्ता)। वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में रही मजबूती के कारण बने दबाव से आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया दो पैसे टूटकर 75.58 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। पिछले दिवस रुपया 75.56रुपये प्रति डॉलर पहर रहा था।

रुपया आज मजबूती के साथ 75.51 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद सत्र के दौरान 75.45 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम और 75.59 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस के 75.56 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में दो पैसे टूटकर 75.58 रुपये प्रति डॉलर पर रहा।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में अधिक रेहड़ी पटरी वाले-अर्थशास्त्री

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो देश की कुल संख्या के मुकाबले एक चौथाई हैं। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा का ऐलान किया है। इसके एक दिन बाद जारी टिप्पणी के मुताबिक दस राज्यों में 35 लाख से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इस योजना से फायदा होगा। इसके मुताबिक बिहार में 5.3 लाख रेहड़ी पटरी वाले, राजस्थान में 3.1 लाख, महाराष्ट्र में 2.9 लाख, तमिलनाडु में 2.8 लाख, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2.1 लाख ओडिशा में 1.7 लाख, हरियाणा में 1.5 लाख और मध्य प्रदेश तथा पंजाब में 1.4 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उनके अनुमान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों से गैर-कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

हर्बल खेती पर खर्च होंगे 4000 करोड़

गंगा किनारे बनेगा औषधीय पौधों का कॉरिडोरः वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की। इस तीसरे हिस्से में उन्होंने कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए राहतों का पिटारा खोला। उन्होंने कहा कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा। सरकार के इस कदम से किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (एनएमपीबी) गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में हर्बल खेती करेगा। इसके लिए यहां एक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। एनएमपीबी की योजना 2.5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय पौधों

की खेती की है। 20 लाख करोड़ रुपये के तीसरे हिस्से का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसान देश का पेट भरने के साथ निर्यात भी करता है। अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादक संघ, कृषि स्टार्टअप आदि का भी इसका लाभ होगा। सभी फलों और सब्जियों तक ऑपरेशन हरित के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष। परिवहन, भंडारण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सीतारमण ने कहा, कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार से किसानों को विपणन का विकल्प मिलेगा। सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी; अनाज, खाद्य तेलों, तिलहनों, दालों, आलू और प्याज को इस कानून के दायरे से नियमन मुक्त किया जायेगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों के दो लाख मधुमक्खी पालकों को होगा लाभ। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों को औपचारिक बनाने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की इससे करीब दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाईयों को लाभ मिलेगा। पशुपालन में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे अधिक दूध उत्पादन होगा और प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाए जाएंगे। नेशनल एनिमल डिजीजी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुंह पका-खुर पका बीमारी से बचाने के लिए जानवरों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इस पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

विश्व बैंक का भारत को एक अरब डॉलर का पैकेज

वाशिंगटन (वार्ता)। विश्व बैंक ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से भारत के सर्वाधिक प्रभावित गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए एक अरब डॉलर का सामाजिक संरक्षण पैकेज मंजूर किया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 14 मई की बैठक में इस पैकेज को स्वीकृति दी। इसे मिलाकर विश्व बैंक की कोविड-19 महामारी चुनौती से निपटने के लिए भारत को दी जा रही मदद दो अरब डॉलर हो गई। एक अरब डॉलर की त्वरित मदद पिछले माह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई थी।

नये पैकेज की राशि दो किस्तों में दी जायेगी। चालू वित्त वर्ष में पहले 75 करोड़ डॉलर का त्वरित आवंटन होगा जबकि शेष 25 करोड़ डॉलर अगले वित्त वर्ष में मिलेंगे।

पहली किस्त की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खर्च की जायेगी जिससे नगदी हस्तांतरण और खाद्य लाभों के क्रियान्वयन में त्वरित मदद मिलेगी। दूसरी किस्त सामाजिक संरक्षण कार्यों पर व्यय की जायेगी।

कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये की योजनायें

नई दिल्ली (वार्ता)। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी रही जिसमें कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया है और इस क्षेत्र के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनायें घोषित की गयी हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आज लगातार तीसरे दिन संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणायें की। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कुछ घोषणायें की गयी थी। पिछले दो महीने में कुछ अतिरिक्त उपाय किये गये हैं। लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74300 करोड़ रुपये की खरीद की जा चुकी है। पीएम किसान के तहत 18700 करोड़ रुपये हस्तातंरित किया जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोल्ड चेन और उत्पादन के बाद प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास के वास्ते फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का एग्रि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्म गेट और एग्रिगेशन केन्द्र पर सुविधायें उपलब्ध कराने पर यह राशि व्यय की जायेगी। इस फंड की शीघ्र ही स्थापना की जायेगी।

मसाला किंग धनंजय दातार यूएई से भारतीयों को स्वदेश भेजने में करेंगे मदद

दुबई ए.। वर्तमान कोविड 19 महामारी के चलते संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हजारों फंसे हुए भारतीयों के लिए आशाजनक खबर है। इन दोनों देशों के बीच हवाई यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है और भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ नामों के पंजीकरण और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अल आदिल ट्रेडिंग के प्रेसिडेन्ट और प्रबंध निदेशक डॉ. धनंजय दातार, भारत वापस आनेवाले जरूरतमंद यात्रियों के हवाई टिकट और कोविड परीक्षण शुल्क में अपना सहयोग दे रहे हैं।

डॉ. दातार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किया गया स्वदेश वापसी का प्रयास महामारी के कारण फंसे लोगों की मदद करने के लिए की गई सबसे बड़ी पहल है। इसे सबसे बड़ी आपातकालीन निकासी में से एक के रूप में देखा जा सकता है और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों की इस संकट में मदद करें।

ऐसे कई लोग हैं जो हवाई यात्रा का किराया और कोविड परीक्षण शुल्क देने की स्थिति में नहीं हैं। डॉ. दातार ने कहा मैं समझता हूँ कि कई लोग जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनके पास आवश्यक पैसा नहीं है। मैं स्वीकृत निकायों के साथ समन्वय करूंगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। इसके संबंध में सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मैंने भारतीय कांसुलेट जनरल श्री विपुल से बात की और भारतीयों के लिए टिकट प्रायोजित करना चाहा। मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी पहल का फायदा होगा। मैं अपने सभी नागरिकों से भी अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रयास करें, ताकि हम इस संकट को जल्द से जल्द दूर कर सकें।

डॉ. धनंजय दातार के नेतृत्व में अल आदिल ट्रेडिंग समूह ने संयुक्त अरब अमीरात में 9000 से अधिक भारतीय उत्पादों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस समूह के खाड़ी देशों में 2 आधुनिक मसाला कारखाने, 2 आटा मिलें और एक आयात-निर्यात कंपनी में फैले 43 विशाल सुपर स्टोर्स की श्रृंखला शामिल है। यूएई के शासकों ने धनंजय को व्यापार क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार और मसाला किंग उपाधि से सम्मानित किया है।

समूह अपने स्वयं के ब्रांड पीकॉक के तहत रेडीमेड आटा, मसाले, अचार, जैम, नमकीन और इंस्टेंट जैसी श्रेणियों के भीतर 700 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करता है।

दो टूक | अमेरिका से बाहर उत्पादन पर लगाएंगे टैक्स - डोनाल्ड ट्रंप

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट करना चाहती है ऐपल

वॉशिंगटन। कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका सहित कई देशों की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट करना चाहती हैं। अमेरिकी कंपनी ऐपल ने भी अपने प्रोडक्शन यूनिट को चीन से भारत ले जाने की बात की है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की बजाय भारत और आयरलैंड जैसे देशों में जाने वाली कंपनियों पर वह नया टैक्स लगा सकते हैं। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐपल के भारत में प्रोडक्शन करने के प्लान को लेकर सवाल पूछा गया था। ट्रंप ने कि कंपनियों को टैक्स प्रोत्साहन दिया गया था, ताकि वे अपने मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को वापस अमेरिका लाएं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के

मुताबिक ऐपल ने कहा है कि वह अपने उत्पादन का एक अहम हिस्सा चीन से भारत शिफ्ट करना चाहती है। चीन के वुहान से कोरोना वायरस फैलने के बाद वहां मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कई टेक कंपनियों का सप्लाई चेन बाधित हुआ है। उन्होंने कहा, ''एपल ने कहा है कि अब वे भारत जाने वाले हैं। वे चीन से हटकर कुछ उत्पादन भारत में करने जा रहे हैं। अगर वे करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम एपल को थोड़ा सा झटका देंगे क्योंकि वे एक ऐसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा किए गए व्यापार सौदे का हिस्सा थी। इसलिए यह एपल के लिए थोड़ा अनुचित है, लेकिन हम अब इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर हम दूसरे देशों की तरह अपनी सीमाओं को बंद कर लेंगे, तो एपल अपने शत प्रतिशत उत्पादों को अमेरिका में ही बनाएगी।'' ट्रंम ने कहा, ''इन कंपनियों को बात समझनी होगी, क्योंकि वे सिर्फ चीन नहीं जा रही हैं। आप देखिए वे कहां जा रही हैं... वे भारत जा रही हैं, वे आयरलैंड जा रही हैं और वे सभी जगह जा रही हैं, वे उन्हें बनाएंगी।'' क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, ''मुझे ऐसा करना है। एक प्रोत्साहन यह है कि जब वे अमेरिका से बाहर उत्पादन करेंगी तो उनपर टैक्स लगाया जाए। हमें उनके लिए अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारे लिए करना है।'' ट्रंप ने कहा कि वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अमेरिका वापस लाना चाहते हैं।

यूपी में विदेशी निवेश लाने की जिम्मेदारी दो मंत्रियों पर

लखनऊ। यूपी में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति निवेश के लिए विभिन्न देशों की कम्पनियों से बात कर उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए संभावनाओं को तलाशेगी। इन कंपनियों का रूख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ने के लिए ये मंत्रीगण उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य एवं संसाधनों तथा उद्योग के अनुकूल वातावरण को दिखाते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार करेंगे।

मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

मुंबई। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त से पहले शुक्रवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 25.16 अंक गिरकर 31,097.73 पर रहा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5.90 अंक नीचे 9,136 पर बंद हुआ। आर्थिक पैकेज के ऐलान की दूसरी किस्त के बाद शेयर बाजार आज सुबह बढ़त के साथ खुला, लेकिन तेजी बकरकार नहीं रह पाई। सेंसेक्स 173.39 अंकों की तेजी के साथ 31,296.28 पर खुला तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38.8 अंकों की बढ़त के साथ 9371.90 पर खुला। हालांकि, कुछ ही देर बाद बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। सुबह 10 बजे सेंसेक्स करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था तो निफ्टी भी 60 अंक नीचे था। घरेलू निवेशकों की धारणा कमजोर होने के बीच एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर घाटे में कारोबार कर रहे थे। एशिया के दूसरे बाजारों में भी गिरावट का दौर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि निवेशक चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा रुख से सचेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन से रिश्ते खत्म करने की बात कही है। पिछले सत्र में बीएसई सेंसेक्स 885.72 अंक या 2.77 प्रतिशत टूट कर 31,122.89 पर बंद हुआ था। शेयर बाजार के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने गुरुवार को पूंजी बाजार से 2,152.52 करोड़ रुपए निकाले।

आज का भविष्यफल

मेषः आपको साक्षात्कार या सौदों के दौरान अपने स्वभाव में नम्रता रखनी होगी। विद्यार्थियों के लिए सफलता के अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए लाभ का दिन है।

वृषभः व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेंगे और आपके पूरे परिवार पर ईश्वर की कृपा होगी।

मिथुनः करियर की प्रगति के संबंध में दिन मध्यम रहेगा। प्रेम संबंधों में उन्नति के आसार हैं और वाहन ध्यान से चलाएं। बाहर जाना अगर जरूरी न हो तो अधिकांश समय घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें।

कर्कः कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। आपका समय अच्छा आएगा।

सिंहः किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाए रखें। अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। परेशानी के इस वक्त में आपको परिस्थितियों का डटकर सामना करने की जरूरत है।

कन्याः कार्यस्थल में किसी से उलझें नहीं। अनावश्यक वार्तालाप इसका कारण बन सकता है। घर पर खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ मस्ती करने को मिल सकती है।

तुलाः अपना धैर्य बनाए रखें। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रति उत्तर देते समय सावधानी बरतें कि कहीं मुंह से कुछ भी गलत न निकल जाएं।

वृश्चिकः दिनचर्या व्यस्त रह सकती है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। धुम्रपान से बचें। परिवार के साथ रहने से सभी समस्याओं का समाधान होगा।

धनुः घरेलू माहौल अनुकूल बना रहेगा, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है।

मकरः यदि आप नौकरी ढूंढ़ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। अति लोभ से बचें। बाहर के खाने से बचें। इस वक्त आपको ही मामले में खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।

कुंभः आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा। जो आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देगा। आपको इस वक्त खुश रहने की कोशिश करनी होगी।

मीनः आपको एक पदोन्नति का अवसर मिलेगा। आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे। दोस्तों के साथ से किसी समस्या का हल निकल आएगा।

सू- दोकू क्र.023

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र[ख] सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.22 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

शब्द सामर्थ्य -023

बाएं से दाएं
1. आय व्यय का लेखा-जोखा, गणित, एकाउंट 3. विनती, अदब 6. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 7. मूल्यवान, बहुमूल्य 8. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 10. बराबर, सम 12. मुख, चेहरा 14. अनुकृति, अनुकरण, असल का विलोम 17. दिमाग, मस्तिष्क 18. मनोहर, सुंदर, इच्छित, प्यारा 19. गर्मी, ताप 21. रसिया, प्रेमी, रसपान करने वाला 23. दबाव, भार 24. भीख 25. काम से जी चुराने वाला, आलसी।

ऊपर से नीचे
1. साहस, वीरता, बहादुरी 2. बहिन, प्रवाहित होना 3. प्रणय क्रीड़ा, सुखोपभोग, हावभाव 4. विश्वास, प्रतीति 5. इंतजार 9. खाने-पीने का सामान, रसद 11. नशीला, मदभरा 12. घायल, जख्मी 13. झुकना, प्रणाम, नमस्कार 14. दृष्टि, निगाह 15. तीव्रइच्छा 16. अर्थ, अभिप्राय, स्वार्थ 20. इम्तिहान, योग्यता आदि को परखना 22. जुल्म, अन्याय 23. पत्नी, बीवी, एक प्रत्यय।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 22 का हल

दा	डी		की		खा	सो	आ	म
वा		त	म	ग्रा			जा	
न	जा	क	त		बा	अ	द	ब
ल		ली		वि	ला	प		हा
	अ	फ	सा	ना		मा	हि	र
दा	ब			श	गु	न		
न		उ	प	का	र		शि	
व		स्व		र		त	क	ला
	सा	व	न		गु	रु	वा	र

मेडिकल स्टोर के गोदाम में लगी आग, मची अफरा-तफरी

नव प्रदेश संवाददाता

मुंगेली। पड़ाव चैक में स्थित एक मेडिकल स्टोर में आग लगी गई। करीब 4 बजे से लगी आग को फायर बिग्रेड की दो गाड़ी ने मुश्किल से डेढ़ घण्टे में काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर की तीन मंजिला दुकान के ऊपर वाली दो मंजिल में आग थी,जिसमें रखी दवाई की जल गई, जिनकी कीमत लगभग 6 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा। आग की घटना से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से अब शॉर्ट सर्किट की समस्याएं सामने आने लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से पड़ाव चैक स्थित गणेश मेडिकल स्टोर की इमारत से अचानक धुंआ उठने लगा ,उठते हुए धुंए को देखकर आसपास लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल दमकल विभाग को दी, धुंए के साथ आग की लपटें इमारत से बाहर निकलने लगी इसी दौरान दमकल विभाग ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया मिली जानकारी के अनुसार गणेश मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग के जिस हिस्से में आग लगी थी उस क्षेत्र में दवाई का गोदाम है। आगजनी से मेडीकल स्टोर संचालक को कितना नुकसान हुआ ये बाद में ही पता चल सकेगा, मेडिकल स्टोर के गोदाम में लगी आग पर यदि सही समय में काबू नही किया जाता तो निश्चित तौर पर जुड़ी हुई इमारत जिसमे रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट संचालित है वो भी आग की चपेटमें आ जाते । बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग की घटना से वहां पर भीड़ का माहौल बन गया सोशल मीडिया में आग की खबर आग की तरह ही फैली जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उतावले लोगो ने पड़ाव चैक पर बड़ी भीड़ जमा कर ली और मोबाइल से वीडियो फुटेज लेने की होड़ लग गयी मौके पर मौजूद पुलिस ने सड़क को वनवे कर जैसे तैसे भीड़ को घटना स्थल से दूर किया ,,, काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नही छोड़ी।

पैदल लौट रहे मजदूरों के बच्चों की व्यथा- थक गए हैं, अब चला नहीं जाता

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। यात्री वाहन प्रतिबंधित होने के कारण श्रमिकों की दिक्कते और बढती जा रही है। वह सैंकडो किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे है। तो इसके साथ ही बडी संख्या में श्रमिक परिवार जिले मे पहुंच रहे है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, तो इसके साथ ही कोई पैदल ही चला जा रहा है, तो कोई साइकिल से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने मजबूर है और इसके साथ ही सुविधा के अनुसार बीच-बीच पर अगर कहीं वाहन मिल जाए, तो वाहन से लिट लेकर अपने घरों तक पहुंचने मजदूर लगे हुए हैं।

शुक्रवार को कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र में पोड़ी के पास लखनऊ से लगभग 13 मजदूर पहुंचे हुए थे। उनके साथ 5 साल व 6 महीने का एक मासूम बच्चा था। मजदूर व उनके साथी अपने सिर पर सामानों का बोझ रखे हुए तपती धूप में पैदल चल रहे थे। साथ में 5 वर्ष का मासूम भी चल रहा था और कह रहा था कि थक गया हूं माँ रुको ना। आज की स्थिति में हर कोई यही चाह रहा है कि कैसे भी हो वह अपने घरों तक पहुंच जाएं। कांपादाह के एक मजदूर परिवार लखनऊ कमाने खाने के लिए गया हुआ था। इस परिवार के सदस्य अंशु ने बताया कि वह लखनऊ में मजदूरी का कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद कार्य बंद हो गया और उन्हें लॉकडाउन के बीच बड़ी मुश्किलों से समय काटना पड़ा। आखिरकार उनके द्वारा खरीदे गए बर्तनों को बेच दिए गए, जैसे-तैसे कर कांपादाह पहुंचने के लिए उन्होंने लगभग 150 किलोमीटर तक पैदल सफर किया, तो कहीं वाहन मिला तो उस पर बैठ गए। इस मजदूर परिवार में दो मासूम बच्चे भी हैं। जिसमें एक की उम्र 5 वर्ष है, तो दूसरे बच्चे का उम्र 5 माह का है और इस तरह वे पैदल ही चलते रहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में फंसे रहने से तो अच्छा है कि जैसे तैसे घर ही पहुंच जाए और वे सब पैदल ही चलने लगे। शुक्रवार के दिन यह सभी मजदूर पोंडी तक पहुंच आए और कांपादाह जाने के लिए वाहनों के इंतजार में बैठे रहे। उन्होंने बताया कि जहां सैकड़ों किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल तय किया। वहीं कहीं-कहीं ट्रक मेटाडोर मिलने पर वे उन वाहनों में बैठकर अपनी दूरी तय करते रहे। 12 तारीख को यह मजदूर परिवार लखनऊ से कांपादाह के लिए निकला हुआ था, जो शुक्रवार को पहुंचा। इसी तरह पंडरिया के पास अंधियारखोर से मेरठ जाने वाले मजदूर भी मिले, जो पैदल ही चले जा रहे थे। इनके साथ में भी दो-तीन बच्चे थे। इन मजदूरों का कहना था कि वे अंधियारखोर गुड़ की फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनका काम बंद हो गया साथ ही ठेकेदार भी बिना मजदूरी राशि दिए छोड़कर चला गया। आखिरकार यह मजदूर भी मेरठ पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि जहां से जैसी सुविधा मिलेगी वह अपने घरों तक पहुंचेंगे। फिलहाल आज की स्थिति में भी बहुत से मजदूर पैदल आते दिख रहे हैं।

जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, माता-पिता के साथ पैदल चल रहे मासूम

धू-धू कर जल उठी इंद्रावती भवन के मुख्य द्वार पर खड़ी कार

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। मंत्रालय के इंद्रावती भवन के मुख्य द्वारा पर खड़ी कार शुक्रवार की दोपहर धू-धू कर जल उठी। मंत्रालय जैसी सर्व सुरक्षा सुविधा से लैस मानी जाने वाली जगह में इस घटना ने सबके कान खड़े कर दिए। कार में लगी आग बुझाने की व्यवस्था करने में इतना समय लग गया कि वह बुरी तरह से जल गई। मंत्रालय के इंद्रावती भवन परिसर में हुई यह घटना कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा कर रही है कि यहां ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेफ्टी मेजर्स के और पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है।

टैंकर-ट्रक में भिड़ंत, 2 की मौत

नव प्रदेश संवाददाता

कोंडागांव। नेशनल हाईवे 30 में कोंडागांव के पास एक सडक़ हादसे में दो ट्रकों की आपस में भिडऩे से दो लोगों की घटनास्थल की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चिखलपुटी के पास भारत पेट्रोलियम की टैंकर व एक ट्रक की आमने सामने भिडंत हो गई। जगदलपुर की ओर से आ रही टैंकर क्रमांक सीजी 04 जेबी 3661 के चालक व कंडक्टर की इस हादसे में मौत हुई है। वहीं राजधानी रायपुर की ओर से जगदलपुर की ओर जा रही ट्रक क्रमांक सीजी 18 एफ0586 में सवार दी तीन लोग घायल हो गये। जिन्हें उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक टैंकर में फंसे शव को क्रेन से निकालने का प्रयास जारी है।

मंत्री सिंहदेव की नर्सरी में हाथियों ने जमाया डेरा

■ ग्रामीणों में मची खलबली, वन विभाग की टीम कर रही मुनादी

नव प्रदेश संवाददाता

अम्बिकापुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के सूरजपुर जिले के खड़गांव में स्थित नर्सरी में 17 हाथियों ने डेरा डाल दिया है। इससे गांव में खलबली मच गई है। नर्सरी के आसपास आबादी क्षेत्र है। हाथियों का दल इस क्षेत्र से गुजर रहा था। इस दौरान अंधेरे हो जाने के कारण हाथी जंगल की ओर नहीं बढ़ सके और मंत्री के नर्सरी में प्रवेश कर गए। नर्सरी के अगल-बगल आबादी क्षेत्र होने के कारण वन कर्मियों द्वारा हाथियों की निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है । खबर है कि 17 हाथियों के झुंड ने अभी तक वहां किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया है।

पखवाड़े भर से 17 हाथियों ने जमाया हुआ है डेरा

17 हाथियों का एक दल पखवाड़े भर से बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के रेवतपुर जंगल में डेरा जमाया था। दिनभर जंगल में रहने वाले हाथी शाम ढलने के बाद नजदीक के खेतों में पहुंच जाया करते थे। हाथियों द्वारा गन्ना, ग्रीष्मकालीन धान और गेहूं की फसल को नुकसान भी पहुंचाया गया। पहली बार इस क्षेत्र में घुसे हाथी पिछले दो दिनों से पुराने रहवासी क्षेत्र मोहनपुर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। ग्रामीणों की घेराबंदी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज्ञात हो कि गुरुवार की रात हाथी जंगल से निकलने के बाद अपने रहवासी क्षेत्र के जंगल की ओर आगे बढ़े। रास्ते में खेतों में खड़ी फसल को खाकर और पैरों से रौंदकर नुकसान पहुंचाया। तड़के हाथियों ने अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग को पार किया, जैसे ही वे जंगल के दूसरी ओर पहुंचे ग्रामीणों की आवाजाही शुरू हो गई।

683 गांवों के 1337 भवनों में रहेंगे प्रवासी मजदूर

■ जिले में अब तक 3 हजार 9 सौ से अधिक श्रमिक क्वारंटाइन

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा बाहर राज्यों से आने वाले श्रमिकों के रुकने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गयी है। जिसके लिए जिला के 6 सौ 83 गाँवो के 1337 चयनित भवनों में होम क्वारटाइन की व्यवस्था पूरी कर लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि हमारे पास वर्तमान में जिला के 6 जनपदों में 91 हज़ार 8 सौ 45 लोगों को रुकवाने की क्षमता तैयार कर लिया गया है।

जिला पँचायत सी ई ओ आशुतोष पाण्डेय ने बताया की सिमगा9हज़ार 6सौ 80, बलौदाबाजार 12 हज़ार 6 सौ 85, भाटापारा 12 हज़ार 7सौ80,पलारी 10हज़ार 6 सौ 80,कसडोल18 हज़ार 2 सौ एवं बिलाईगढ़ 27 हज़ार 8 सौ 20 इस तरह कुल 91 हज़ार 8 सौ 45 लोगो को वर्तमान में रुकवाया जा सकता है।.लगातार अन्य राज्यों से मजदूरों का आना जारी है। उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार बकायदा स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके नजदीकी गाँवो में प्रशासन की ओर से पहुँचा कर उन्हें निर्धारित भवनों में 14 दिनों के लिए क्वारटाइन किया जा रहा है। कल दोपहर 12 बजे तक बाहर राज्यों से आये जिला के कुल 3 हज़ार 9सौ 53 श्रमिकों को निर्धारित भवनों में क्वारटाइन किया गया है। जिसमें सिमगा के3 सौ49,बालौदा बाजार में 1हज़ार 1सौ84,भाटापारा 5 सौ 55 ,पलारी 8 सौ 35, कसडोल 3 सौ 3 एवं बिलाईगढ़ 7 सौ 27 लोग शामिल है।इसके लिए पंचायत विभाग अलग से कार्य कर रहा है। गाँवो के जिन भवनों में क्वारटाइन किया गया है। वहाँ की व्यवस्था सरपंच सचिव के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन लोगों की भोजन एव सहायता के लिए सम्बंधित गाँव वाले भी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे है।यह सभी लोग 14 दिन भवनों में ही रुककर अपना अपना खाना बनाकर भोजन प्राप्त कर रहे। यह लोग बाहर ना आ जाये इसके लिए इन भवनों के बाहर ताला लगा कर सतत निगरानी गाँवो वालो के तरफसे भी किया जा रहा है। गाँव वाले भी इन लोगो को दूर से ही हरी सब्जियां आदि अपने सहयोग से प्रदान कर रहे है।

अन्नपूर्णा रथ से प्राप्त राशन से मिल रही है मदद

जिला वासियों के सहयोग से सभी जनपदों में अन्नपूर्णा रथ आन काल डोनेशन वेन चलाया जा रहा है। जिसमें जिला वासियो द्वारा बड़ी मात्रा में सुखा राशन दान किया जा रहे है। इन से प्राप्त राशन को ही निर्धारित मात्रा में पैकेट बना कर जनपदों के माध्यम से इन क्वारटाइन सेंटर तक पहुँचाया जा रहा है। जिससे इन श्रमिकों को भोजन मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य की भी सतत निगरानी

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों मितानिन,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन सभी मजदूरो की स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी किया जा रहा है। ताकि अगर इन मजदूरों को भी सामान्य तकलीफ हो तो उनका मदद कर सके।

30 जून तक नियमित चलने वाली सभी ट्रेन रद्द, सिर्फ स्पेशल चलेगी

भाटापारा। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने हेतु रेल मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की पूरे भारतीय रेल्वे में दिनांक 30 जून, 2020 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी एक्सप्रेस ट्रेनों एवं मेमू लोकल एवं पैसेंजर गाडियों को दिनांक 30 जून, 2020 तक रदद किया गया है। विशेष मार्गों पर 12 मई, 2020 से विशेष रेल सेवाओं की शुरुआत की गई। स्पेशल ट्रेन स्पेशल टाइमिंग के साथ चलेगी। ये विशेष सेवाएं फंसे हुए लोगों एवं श्रमिको के लिए चलाई जा रही सेवाए जारी रहेगी । इसी क्रम में 30 जून 2020 तक सभी मेल / एक्सप्रेस एवं मेमू लोकल एवं पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। यात्रियो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी रद्द की गयी गाड़ियो का पूरा रिफ़ंड रेल्वे नियमो के अनुसार लिया जा सकता है ।